SHORT DURATION DISCUSSION ON THE PRE-BUDGET HIKE IN THE PRICES OF COAL AND SUGAR

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, कोयले और चीनी के मूल्य में बजट पूर्व वृद्धि के संबंध में अल्पकालिक चर्चा में प्रारम्भ करना चाहता हूं। कोयले और चीनी के मूल्य बढ़ाने के कारण (**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : मेरा एक सबमिशन है। (**व्यवधान**) मेरा सबमिशन यह है कि पांच बज रहे हैं इसलिए हाऊस को एडजर्न होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (**श्री मोहम्मद सलीम**) : कोयले और चीनी की कीमत का सवाल है, सुन लीजिए (**व्यवधान**)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): No decision has been taken in the BAC to extend the time.

उपसभाध्यक्ष (**श्री मोहम्मद सलीम**) : मेरे ख्याल से यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सुबह से सदस्यगण चाह रहे थे कि इस पर चर्चा हो। दर असल पांच बज चुके हैं लेकिन कोयले और चीनी के भाव का सवाल है, अगर हाऊस चाहता है तो हम ले सकते हैं। मेरा ख्याल है आप थोड़ा बोले, ज्यादा न बोलें तो हो सकता है।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL SHRI AJIT KUMAR PANJA: We are in one difficulty. Tomorrow in the Lok Sabha, it has been fixed up.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: We are not concerned with the Lok Sabha. पहले दिन कभी एक्सटेन्ड नहीं हुआ।

SHRI AJIT KUMAR PANJA: Tomorrow in the Lok Sabha, it has already been fixed up. When I mentioned that this has been fixed up today here in this House, in the Lok Sabha it has been fixed up for tomorrow. So, I will be in difficulty, Sir.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (**डा. अबरार अहमद**) : कल से मोशन आफ थैंक्स शुरू होगा। इसको आज ही लिया जाये। (**व्यवधान**) इसको आज लेना है। (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Let us start it. If the hon. Members feel any difficulty, we will see. Let us start now.

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): It is already 5 O'Clock. Let the House be adjourned.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We have already started a discussion on it. We will conclude by 7.30 today (*Interruptions*) you please continue.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: No, Sir.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Nowhere in the history on the first day we exceeded the time limit. There was no decision about it in the BAC.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): I have a point, Sir. Tomorrow, we will have the Motion of Thanks on the President's Address. That will be the first item to be taken up tomorrow Discussion on it is for three days. Then you will have to continue it next week after Tuesday. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) This is up to the House. We should take it up today or tomorrow. Let us go by the rules. I would like to know whether the Members are interested to discuss the price rise on coal and sugar this evening.

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : आज ही होना चाहिये। (**व्यवधान**)

डा० अबरार अहमद। यह तय हुआ था कि आज ही इसको लिया जाय (**व्यवधान**)

श्री विष्णु कांत शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : इतना महत्वपूर्ण विषय है जो इन्होंने शुरू किया है (व्यवधान) कल इसको लिया जाय (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : हमारी यह भावना है कि पहले भी महत्वपूर्ण सवाल सदस्य उठाना चाहते थे और यह चाहते थे कि उन पर बहस हो लेकिन मौका नहीं मिल पाता है और मामला आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता रहता है । कल से तो मोशन आफ थैंक्स के बारे में चर्चा होगी तो इस डिसक्शन को हम ले नहीं पायेंगे । यह डिसक्शन प्रि-बजट हाईक इन प्राइसेज के बारे में है इसलिये इस पर डिसक्शन होना चाहिये । इसलिये यह सदस्यों के ऊपर है कि वह महंगाई के ऊपर बात करना चाहते हैं या नहीं । (व्यवधान)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: The Short Duration Discussion should be taken up tomorrow. We cannot extend the time limit today. This is an important issue before the house.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में टाईम एक्सटेंड करने के बारे में कोई भी डिसिजन नहीं लिया गया है । नार्मली जो बुलेटिन में समय आता है वह 11 से पांच बजे तक का होता है जब तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अदरवाइस तय न करे The House is bound by the timing.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : भंडारी जी ऐसा नहीं है ।

डा० अबरार अहमद : कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने डिसिजन लिया था । (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : बी०ए०सी० में बात हुई यह कहा गया कि महत्वपूर्ण विषय है इसको लेना पड़ेगा लेकिन समय का सवाल है । (व्यवधान)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: No, I was here.

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कोई डिक्शन नहीं किया गया । उसमें आप थे (व्यवधान) आप भी थे (व्यवधान)

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): Generally on a day like this, when we take up a calling attention like this, we would be sitting beyond 5 O'Clock. It all depends upon the consensus of the House. This is not the first time we are sitting late. Always, if the entire House agree, we sit beyond 5 O'Clock.

डा० अबरार अहमद : कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह बात तय हुई थी कि इन दोनों बिलों के समाप्त होने के बाद कल ही यह लिया जायेगा और कल ही समाप्त किया जायेगा । (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह गलत बात है । यह नहीं कहा गया था (व्यवधान) यह कहा गया कि कल लिया जायेगा । (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : माथुर साहब, यह बहस का विषय नहीं है । आप मंत्री जी को बोलने दीजिये । (व्यवधान)

डा० अबरार अहमद : कल यह बिल्कुल स्पष्ट तय हुआ था कि 24 तारीख से प्रेजीडेंट एड्रेस पर थैंक्स का मोशन शुरू होगा और यह एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसज का आज दोनों बिलों के बाद लेना था और आज ही समाप्त करना था । 24, 25 और 1 ये तीनों दिन प्रेजीडेंट एड्रेस के लिये तय हुये थे । बिल्कुल क्लियर यह बात तय हुई थी और एकाडिगली इसको आज ही लेना चाहिये (व्यवधान) इतने महत्वपूर्ण मसले पर आप आज बहस नहीं होने देंगे . . . (व्यवधान)

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Mr. Vice-Chairman, Sir, generally on a day like this when we take up the Short Duration discussion, we sit beyond 5 O' clock. It all depends upon the consensus of the House. This is not the first time we are going to do it. If the entire House agrees, we will sit beyond 5 o'clock. If the consensus of the House is that we should sit beyond 5 o'clock, let the hon. Member start the discussion on this issue and let us adjourn at 6 o'clock. If the discussion is not completed, we can take it up tomorrow.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, I want to say something. First of all, we cannot discuss what has happened in the Business Advisory Committee. It is not done.

Secondly, we all know that it is listed in today's revised List of Business. If they feel that the discussion on this subject is that important. I think, we should take it up. There is no question that on the first day you have to go home by 5 o'clock. It is already ten minutes past five of the clock. If the House in its wisdom decides to sit beyond and continue the discussion, then, we can do it. Nobody can prevent us from speaking and hearing.

Thirdly, if Mr. Mahajan does not want to continue today, he cannot insist that it should be taken up tomorrow because the Motion of Thanks to the President's Address takes precedence over it. He can either finish it today or on Tuesday or Wednesday whenever time permits. He cannot insist that it should be taken up tomorrow. That is not fair.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, my point is that it is reasonably an important issue. But I must say from what I have gathered from the speech of the Minister of Parliamentary Affairs that its time was fixed rather in a peculiar manner, that after the two Bills this has to be taken up and has to be completed today... (*Interruptions*)... I am not disputing it.

Then, even if Mr. Pramod Mahajan finishes his speech on the Short Duration discussion, it cannot be completed because most of the speakers, listed speakers I should say, are not present in the House on the understanding that on the very first day it will not be completed... (*Interruptions*)... Therefore, I say we will have to take it up sometime later. The debate on the Motion of Thanks to the President's Address will begin from 24th and will continue up to the 1st of March. Only thereafter this issue may be taken up. By that time, the Budget will be presented. This momentum will be lost. But that way the time has been fixed. I should say, has been done very cleverly. It was a very clever strategy to sabotage the discussion on Short Duration.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: It appears that Mr. Mathur and Mr. Mahajan are not serious about it. If they do not want, they need not press for it.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: You are very serious of increasing the prices.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: You have created this problem of increasing the prices.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: You cannot demolish a public sector unit.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: वाइस चेयरमैन साहब, अबरार साहब दो बार बोल चुके हैं। दो मंत्री खड़े हो चुके हैं। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। पहली बात, पंजा साहब तो बी.ए.सी. मीटिंग में नहीं थे .... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): तीसरे मंत्री खड़े होने के लिए तैयार हैं मैं मैं उन्हें नहीं दिया है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: बी.ए.सी. मीटिंग में कल्पनाथ जी नहीं थे। अबरार साहब थे... (**व्यवधान**)

अबरार साहब का कहना यह है, जो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है कि यह तय हुआ था कि इसको आज ही खत्म किया जाए। अगर यह तय होता तो जो अक्षरश: ... (**व्यवधान**) आया है उसमें एक्सटेंड टाइम दिया होता 5.00 बजे के बाद तक हाउस बैठेगा, वह नहीं दिया गया है। क्या आज आप रात के ग्यारह बजे तक बैठकर.... (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य: प्वाइंट आफ आर्डर .... (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: आप मुझे पूरा करने दीजिए।.... (**व्यवधान**) यह क्या तरीका है?

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : बात खत्म कीजिए । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं खत्म कर रहा हूं । . . . (**व्यवधान**) मैं कह रहा हूं कि क्या रात के दस बजे तक बैठ करके आज यह खत्म होगा ? अगर यह खत्म नहीं होगा तो फिर बाद में क्यों बैठें ? खत्म होने की बात बता दें । . . . . (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You have communicated your idea that unless it can be finished today, we should not take it up. Now let us hear the point of order.

श्री सैयद शिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश) : हमारे हाउस की ट्रेडीशन यह है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो डिसकस होता है वह बाद में हाउस में डिसकस नहीं होता । लेकिन बराबर वही प्रक्रिया चल रही है । मेरा आपसे अनुरोध यह है कि क्योंकि यह मसला बहुत इंपार्टेंट है और इसीलिये इस मसले को यहां पर लाया गया है, इसकी सारी रेलेवेंसी खत्म हो जायेगी, आज ही डिसाइड होना चाहिये । हाउस का मत भी यही है, आज ही इसको डिसाइड करके खत्म करिये । कल हम प्रेसीडेशन एड्रेस पर अपना काम शुरू करेंगे और आप इस मामले में ज्यादा वक्त बर्बाद न करने दें इन लोगों को और इतना अनुरोध करेंगे कि जो अपनी बात कहना है ब्रीफ में कह दें । यह महत्वपूर्ण विषय है इसलिये इसको लाइटली क्यों बना रहे हैं ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आज खत्म होगा ? क्या आज आप इसे खत्म करेंगे? . . . (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : आप भी बोल दीजिये मि. सेन । . . . (**व्यवधान**)

SHRI AJIT KUMAR PANJA: We can finish it by 6 o'clock.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जो लिस्ट आफ बिजनेस है . . . (**व्यवधान**) क्या गुरूदास दास गुप्त यहां मौजूद हैं ? . . . (**व्यवधान**)

DR. ABRAR AHMED: I can assure you that today we will finish it.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Yesterday. . . . (*Interruptions*). Tomorrow, the discussion on the Motion of Thanks to the President's Address will start. Then, many things will happen in the country and so many discussions will be thrust on the House whether you want it or not. It is better to discuss the matter for two hours and finish it today.

श्री प्रमोद महाजन : उपसभाध्यक्ष जी, कोयला और चीनी तथा अन्य उत्पादों के मूल्यों में बजट पूर्व वृद्धि करने वाली यह सरकार यदि स्मरण रहे तो इस वायदे पर चुन कर आई थी कि यह 100 दिन के अन्दर हिन्दुस्तान में महंगाई कम करेगी (**व्यवधान**) अब आप बोलने भी देंगे ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उनकी आदत है । आदत से मजबूर हैं ।

श्री प्रमोद महाजन : महंगाई की मार तो है ही और फिर आपकी मार । . . . (**व्यवधान**) आज महंगाई की आग में जो सर्वसाधारण जनता जल रही है, इसका अगर सबसे अधिक प्रमुख दोष किस पर आता है . . . (**व्यवधान**)

कई माननीय सदस्य (बी०जे०पी० वालों पर . . . (**व्यवधान**)

श्री प्रमोद महाजन : उपसभाध्यक्ष जी, अगर इस प्रकार बोलना है तो मुझे बोलना नहीं है । मैं कभी किसी के बोलने में मजाक तरीके से सोचता नहीं हूं । जयन्ती जी होनी तो अच्छा होता । . . . (**व्यवधान**)

श्री विष्णु कांत शास्त्री : यह बहुत जरूरी है, गंभीर मामला है ।

SHRI PRAMOD MAHAJAN: She was talking about the seriousness of the discussion. Are they serious persons sitting here?

(*Interruptions*).

श्री विष्णु कांत शास्त्री : वह कांग्रेसी गंभीरता है। . . . (व्यवधान)

SHRI AJIT KUMAR PANJA: Whenever Pramod Mahajanji gets angry, he speaks in English, otherwise in Hindi.

श्री प्रमोद महाजन : यह तरीका नहीं है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिससे कोई चोट पहुंचे। और इसके पश्चात् आखिर बोलने वाला अपनी तैयारी से आता है। अब मैं मानता हूं कि मेरे पास उनके जितनी विद्वता नहीं है और जितनी भी है उस पर मैं कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूं। जो इस प्रकार का परिहास मुझे ठीक नहीं लगता।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि महंगाई आज इस देश में जो चरम सीमा तक पहुंची है, उस चरम सीमा तक महंगाई को ले जाने में अगर इस देश में किसी एक संस्था का प्रमुख दोष है, तो हिन्दुस्तान की वर्तमान सरकार का प्रमुख दोष है, क्योंकि इस देश में महंगाई बढ़ाने वाली जितनी आधारभूत वस्तुएं है, उन आधारभूत वस्तुओं की कीमत, उनका मूल्य केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। महोदय, कम से कम 16 ऐसी प्रमुख वस्तुयें हैं, जोकि महंगाई को और महंगाई के चक्र को जन्म देती हैं। इन सारी वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण केन्द्र सरकार करती है और इसलिये जिस महंगाई से आज जनता जूझ रही है, वह महंगाई कोई एक आर्थिक विशेष परिस्थिति का परिणाम नहीं है। यह इस सरकार की गलत नीतियों के कारण है। जिस प्रकार से इन्होंने ऐसी वस्तुओं जिन पर कि इनका नियंत्रण है, ऐसी सरकारी नियंत्रित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कर के महंगाई के एक चक्र को जन्म दिया है, यह इनकी उन गलत नीतियों के ही कारण है।

उपसभाध्यक्ष जी, अगले शनिवार की 27 तारीख को हिन्दुस्तान का बजट आने वाला है और गत कुछ वर्षों से हमारे देश में यह गलत परम्परा पड़ी है कि जैसे बजट आता है, बजट आने से पहले सप्ताह में सरकार अपनी नियंत्रित वस्तुओं के दाम बढ़ाने प्रारम्भ कर देती है मानो वस्तुओं के दाम बढ़ गए तो समझ लेना कि बजट की तिथि निश्चित हुई। इस प्रकार का एक इतिहास बना है, महोदय, सरकार जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भारतीय अर्थ-नीति की अनगिनत वस्तुओं का निर्धारण करती है तो यह निर्धारण मुख्य रूप से बजट में हो, यह अपेक्षा है। कुछ वर्षों में पूर्व हिन्दुस्तान में बजट एक ऐसी स्थिति थी, जिसमें कि आर्थिक स्थिति का प्रतिबिंब होता था--महंगाई बढ़ना-घटना, वस्तुओं के दाम निश्चत होना--अनिश्चित होना, कम होना, ज्यादा होना, एक समय में बजट में आता था और इसीलिये शायद उसके लिये शब्द बजट होता था और उसके बाद एक वर्ष तक उस निर्धारित बजट के आधार पर सरकार चलने का प्रयास करती थी। लेकिन अब यह लगता है कि बजट आने से पूर्व ही अपने संसाधन बढ़ाने के लिये सरकारें, मैं केवल इस सरकार और अभी की सरकार नहीं कहूंगा, गत कुछ वर्षों से यह परम्परा पड़ी है कि सरकारें अपनी नियंत्रित वस्तुओं के दाम बजट पूर्व बढ़ाकर सारे बजट की पवित्रता को समाप्त कर देती है, बजट के महत्व को समाप्त कर देती है और बजट लगभग बेईमानी बनकर रह जाता है। इस प्रकार बजट का अवमूल्यन, इस प्रकार की नियंत्रित वस्तुओं के दाम पहले ही बढ़ाने का कार्य सरकार करती है। इसलिये यह सवाल केवल कोयले या चीनी का नहीं है, केवल पैट्रोलियम पदार्थों का नहीं है, सरकार की नीति के साथ यह जो गलत नीयत जुड़ी है। यह नीयत जिसके कारण कि गत वर्ष का बजट घाटा पूरा करने के लिये, यह आंकड़ों की जादूगरी

करने के लिये दो-चार-पांच सप्ताह पहले अपने संसाधन बढ़ाने का जो प्रयास होता है, पहले तो मुझे लगता है कि यह धिक्कार-योग्य है, निर्णय योग्य है और इस प्रकार का प्रयास दुर्भाग्य से इस वर्ष भी किया है। इसलिये यह महंगाई अपनी अर्थनीति निर्मित नहीं है बल्कि मुख्य रूप से सरकार की ओर से आती है, सार्वजनिक क्षेत्रों की ओर से आती है और सार्वजनिक क्षेत्र क्योंकि सरकार नियंत्रित होते हैं, यह महंगाई को जन्म देते है। इसलिये मुख्य रूप से बजट की पवित्रता, महत्व और बजट की विशेषता समाप्त करने के लिये मैं इस सरकार को सबसे पहले दोष देना चाहूंगा। अब जिन दो वस्तुओं के संबंध में उन्होंने महंगाई का नियंत्रण किया है, उसमें सबसे पहले आता है चीनी। अचानक सरकार ने चीनी का दाम, खासकर जो राशन में मिलती है, 1 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम बढ़ा दिया है। अब यह बढ़ाने के बाद, जमाना एक था जब चीनी का नाम लेते थे तो मुंह में पानी आता था और यह दाम बढ़ने के बाद चीनी का नाम लेते है तो गरीब आदमी की आखों में पानी आता है। तो पानी का परिवर्तन मुंह से आखों में करने का प्रयास इस चीनी नीति के अंतर्गत इस सरकार ने किया है। सरकार की चीनी उद्योग के संबंध में नई नीति घोषित हुई है। अब उसके अनेक बिन्दु है, लेकिन मुख्य रूप से मैं आज उससे निर्मित होने वाली महंगाई के संबंध में बात करूंगा, अन्य संबंध में अभी नहीं जाऊंगा। इसमें कुछ विशेषताएं कुछ अच्छाइयां हैं, लेकिन उसके साथ-साथ सरकार ने राशन के अंतर्गत आने वाली दुकानों पर चीनी का दाम 6 रुपए 90 पैसे प्रति किलो से बढ़ाकर 8 रु० 10 पैसे प्रति किलो कर दिया है। यह वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि है, जो अप्रत्याशित है। इसके पहले चीनी का दाम इस प्रकार एक ही झटके में कभी बढ़ाया नहीं गया था। यह तो राशन की दुकान की स्थिति है। बाजार में आज चीनी का दाम जो 11 या 12 रुपए प्रति किलो के आसपास है, इस नीति के अंतर्गत यह बढ़कर 14/15 रुपए किलो तक होने की स्थिति, होने की संभावना स्पष्ट दिखाई पड़ती है।

मान्यवर, अब चीनी के जो दाम बढे हैं, इसके बढ़ने का कारण जो केन्द्र सरकार ने दिया है, उसमें केन्द्र सरकार मुख्य रूप से यह कहती है कि सरकार ने गन्ने के खरीद मूल्य में 31/–रुपए प्रति क्विंटल से 32 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल बढौतरी की है। सरकार का दावा यह है कि गत वर्ष 26/–रुपए से 31/–रुपए तक बढ़ौतरी की थी और सरकार का आगे यह कहना है कि 26/-रुपए से लेकर 32 रुपए 50 पैसे तक, इसका अर्थ यह हुआ कि 6 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल गन्ने की लागत में वृद्धि की, उस समय चीनी के दाम बढ़ाए नहीं थे और चूंकि हमने यह दूसरी बार वृद्धि की है और अब कुल वृद्धि साढ़े छह रूपए के आसपास हुई है तो राशन पर चीनी के दाम बढाना हमारे लिए अनिवार्य हो गया था। इस प्रकार की भूमिका लेकर सरकार ने चीनी के दाम राशन की दुकान पर बढ़ा दिए हैं।

[उपसभाध्यक्ष श्री सैयद सिब्ते रजी पीठासीन हुए]

मान्यवर, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि गन्ने के खरीद मूल्य में सरकार ने जो वृद्धि की है, उस वृद्धि का हम स्वागत करते हैं। गन्ने की खरीद मूल्यों की वृद्धि गलत है, यह मैं नहीं मानता। मैं तो इसके आगे जाकर यह कहना चाहूंगा कि गन्ना किसान का एक प्रमुख उत्पाद है और इस उत्पाद का मूल्य तय करते समय उत्पादन खर्च का आधार जोड़कर, इसका एक कोई वैज्ञानिक रूप बनाकर मूल्य निर्धारण करना चाहिए। इसलिए सरकार ने अगर 32 रुपए 50 पैसे तक गन्ने के मूल्य में वृद्धि की है, तो मैं यह मानता हूं कि यह उचित कदम है, लेकिन....

खाद्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : स्वागत है।

श्री प्रमोद महाजन : मैंने पहले ही स्वागत किया। यहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, किसान के शोषण पर आधारित किसी भी कृत्रिम अर्थव्यवस्था का भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करना चाहती और इसलिए किसान को उसके गन्ने का उचित मूल्य मिले, यह उचित कदम है, लेकिन उसके साथ-साथ क्या 6 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल गन्ने का

[श्री प्रमोद महाजन]

मूल्य बढ़ाने के कारण राशन की दुकान पर चीनी का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा प्रति किलो बढ़ाना जरूरी होता है ? मैं यह चाहता हूं कि अगर मंत्री महोदय अपने उत्तर में इस बात का विश्लेषण कर दें तो वह अधिक अच्छा ही होगा क्योंकि 6 रूपए 50 पैसे, मैं दो वर्ष का इक्कठा गिन रहा हूं, केवल इस वर्ष का नहीं गिन रहा हूं, लेकिन जबसे आपने चीनी के दाम नहीं बढ़ाए, अब इसमें सरकार की चतुराई देखिए कि 60 प्रतिशत चीनी यह मुक्त बाजार में जाएगी। जिसके मूल्य पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, बाजार का नियंत्रण होगा। इसलिए गन्ने के खरीद मूल्य में जो 6 रुपए 50 पैसे की गत दो वर्ष में वृद्धि की है, उस वृद्धि से निर्मित होने वाली चीनी का अधिकांश 60 प्रतिशत हिस्सा बाजार में चला जाएगा जिसका दाम एक रूपये 40 पैसे नहीं, तीन से चार रुपए किलो तक बढ़ने की संभावना है और जब हम 50 लाख टन चीनी बेचते हैं तो यह पूरा खेल लगभग डेढ़ करोड़ रुपए का होता है, अब उसके साथ-साथ अधिकांश चीनी तो उस ग्राहक को उठानी पड़ती है जो बाजार से लेता है। अब सरकार को गरीब ग्राहक का बोझ उठाना है। अब जो 40 प्रतिशत चीनी राशन की दुकान पर जाती है, वहां से गरीब आदमी खरीदता है, यह भी नियंत्रित रूप में खरीदता है, उसका अनुपात निश्चित होता है, जो चाहे जितना वह खरीद नहीं पाता। अब यह जो 40 प्रतिशत, अब यह जो दोहरी नीति हमने बनाई है, मैं सबसे पहले तो सरकार से यह आग्रह करूंगा कि राशन कार्ड की स्थिति में यह जो दोहरी नीति है इस पर सरकार थोड़ा पुनर्विचार करें क्योंकि राशन कार्ड आज सबके पास होते हैं और राशन कार्ड का उपयोग अमीर आदमी नहीं करता लेकिन उसका दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए राशन पर मिलने वाली चीजों में से अधिकांश चीजें केवल गरीब को मिलें, इस प्रकार की व्यवस्था कुछ प्रदेशों में सोची जा रही है। मैं महाराष्ट्र में उस प्रकार का प्रयास जानता हूं कि जिसमें उन्होंने गरीबों के लिए राशन कार्ड और अमीरों के लिए राशन कार्ड, इसमें एक अंतर करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि इस विषय में भी एक राष्ट्रीय मन, एक राष्ट्रीय मत बनाने के लिए सरकार जरूर प्रयास करेगी। अब यह जो चीनी का उपयोग है, जिसमें आप 60 प्रतिशत इसमें लाते हैं, अब मैं इसका हिसाब उपाध्यक्ष जी लगाने का प्रयास कर रहा था। हमने प्रति क्विंटल 6 रुपए 50 पैसे बढ़ाया है और एक क्विंटल, मतलब 100 किलो गन्ने से हमारे यहां जो आपने उसका रिकवरी मूल्य पकड़ा है, वह है 8.5, साढ़े आठ किलो। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में कई कारखाने हैं जो इससे नीचे आते हैं, महाराष्ट्र में कई कारखाने हैं जो 10-11 किलो तक चले जाते हैं, लेकिन 100 किलो गन्ने से निर्मित चीनी, यह होती है ओन एन एवरेज साढ़े आठ किलो। अगर सौ किलो गन्ने का मूल्य साढ़े छः रुपए तक गत तीन वर्षों में बढ़ा दिया है, तो इसका अर्थ यह हो गया कि साढ़े आठ किलो जो चीनी है, वह साढ़े आठ किलो–मैं एक किलो की बात नहीं कर रहा हूं–साढ़े आठ किलो चीनी का मूल्य कुल मिलाकर आपने साढ़े छः रुपए बढ़ाया है, साढ़े छः से बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसके साथ-साथ आप पहला यह भी हिसाब ध्यान रखें कि इसमें से 60 प्रतिशत बाजार में चला जाता है और बाजार में आपके राशन की दुकान से ज्यादा बिकता है। इसका अर्थ यह स्पष्ट है कि अगर आप कोई हिसाब लगाने का प्रयास करें तो प्रति किलो गन्ने के मूल्य में वृद्धि होने के कारण, जो अभी आपने की है और आप थोड़ा और भी कर दें तो उसका असर चीनी के एक किलो पर 60–65 पैसे से अधिक नहीं होता और अगर वह 60–65 पैसे से अधिक नहीं होता तो आप चीनी का मूल्य एक रुपए चालीस पैसे से बढ़ा कर ग्राहकों को यह बता रहे हैं कि चूंकि हमने किसानों को अधिक मूल्य दिया, इसलिए आपको अधिक दाम में चीनी खरीदनी पड़ेगी। सबसे पहली तो मेरी प्रार्थना यह होगी कि जो गरीब हैं, मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा हूं, वह बाजार से चाहे जितने दाम में खरीदें, लेकिन जो गरीब आदमी अपने त्यौहार के लिए चीनी खरीदना चाहता है, उसकी

चीनी को तो सरकार को सबसिडाइज्ड करना चाहिए, उसकी चीनी तो उसको सस्ते में मिले। इसलिए सरकार को खुद थोड़ा घाटा उठाकर नान लेवी शूगर में उस पैसे को वसूल करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आपने मान लिया कि यह नहीं किया। आप अगर बढ़े हुए गन्ने का मूल्य पूरे का पूरा ग्राहक के सिर पर डालना चाहते तो राशन की दुकान से, तब भी यह मूल्य 65 पैसे से अधिक हो नहीं सकता। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आपने एक रुपया चालीस पैसे, मतलब अपने किसान को जितना दिया उसमें से 60 प्रतिशत बाजार गया, 40 प्रतिशत राशन की दुकान में आया और इस हिसाब से 50 पैसे प्रति किलो चीनी पर भी आपने किसान को ज्यादा नहीं दिए तो आप डेढ़ रुपए के आसपास क्यों बढ़ा रहे हो और इसलिए मैंने प्रारम्भ में कहा कि यह किसान और ग्राहक के बीच में आपकी जो व्यवस्था खड़ी है उस व्यवस्था में मुझे लगता है कि जरूर कोई न कोई ऐसी चीज बनी है जिसके कारण किसान को तो गन्ने के मूल्य कम मिल रहे हैं लेकिन ग्राहक को तो बढ़े हुए दाम पर चीनी लेनी पड़ रही है और इसलिए करोड़ों किसान नाराज हैं क्योंकि गन्ने का मूल्य नहीं मिलता और करोड़ों लोग नाराज हैं क्योंकि महंगी चीनी लेनी पड़ती है। मैं यह चाहता हूं कि एक नई चीनी नीति जो घोषित की है उसमें और कुछ विचार का स्थान हो तो किसान और ग्राहक के बीच में खड़ी दीवार अगर तोड़ दें तो मुझे लगता है कि उत्पादन करने वाला और खरीदने वाला उस महंगाई से बच सकता है लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रकार का विचार इसमें नहीं है इसलिए मैं इससे जुड़ी दो बातें जोड़कर कहना चाहूंगा कि आपने लगभग दो सौ नई चीनी मिलों के एक्सपेंशन की बात की है। आपने कुछ चीनी मिलों को अनुमति भी दी है। लेकिन दुर्भाग्य से आप चीनी मिलों को जो अनुमति देते हैं उन चीनी मिलों को बाद में वित्तीय संस्थायें पैसे नहीं देती और इसलिए आपकी अनुमति देने के बाद भी यह मिल कभी खड़ी नहीं होती और मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि चीनी मिल अगर इंडस्ट्री है तो वह फूड के अन्तर्गत क्यों आती है। इंडस्ट्री को लाइसेंसिंग देना यह फूड मिनिस्ट्री से क्यों जोड़ा गया है, यह मेरी समझ में नहीं आता कि दुनिया की सारी इंडस्ट्री अगर इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से जोड़ी हैं तो हमने इसको फूड के अंदर क्यों डाला है। लेकिन कम से कम आप केवल अनुमति पत्र न दें। वित्तीय संस्थायें उन्हें किस प्रकार का वित्त उपलब्ध करें, इस पर भी विचार करें।

इसके साथ-साथ मैं चीनी के दामों के बारे में यह कहना चाहूंगा कि हमने लगभग 20 साल पहले चीनी की दोहरी नीति को सोचा था–एक राशन में और एक बाजार में। मुझे लगता है कि समय यह आ गया है कि सरकार इसका अध्ययन करे कि–क्या हम चीनी मिलों को डि–लाइसेंसिंग कर सकते हैं। अगर हम उदारीकरण की ओर बढ़ रहे हैं तो जो व्यक्ति चीनी मिल खड़ी करना चाहते हैं, जो संस्थायें चीनी मिल खड़ी करना चाहती हैं उन व्यक्तियों और संस्थाओं को हम अपनी जितनी संभव मदद करें और वह खड़ा करने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि चीनी का उत्पादन भी बढ़ेगा। आज हमको इसकी भी शिकायत आती है कि चीनी नहीं मिल रही है और किसान का गन्ना, फसल वैसी ही खड़ी है, उसकी क्रासिंग नहीं हो रही है। खासकर आप जिस एरिया से आते हैं उसमें तो ज्यादा क्रासिंग की प्रोब्लम है। क्रासिंग नहीं होती है तो उसकी चीनी कम होती जाती है और इसको देखते हुए अगर आप मिलों के डि–लाइसेंसिंग का सोचें और उसके साथ-साथ यह डुवेल पालिसी छोड़कर अगर हम और चीजों जैसा इसको बाजार के द्वारा नियंत्रित करें और संकट आने पर बफर स्टाक मुक्त करें, इस प्रकार की अगर कोई नई नीति आप सोचेंगे तो मुझे लगता है कि जनता पर आप जो चीनी के द्वारा महंगाई का बोझ डाल रहे हो तो इस बोझ को कम करने का प्रयास आप कर सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं चीनी के बाद संक्षेप में कोयले पर आना चाहूंगा । वैसे यह दोनों विषय एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं । आप कोयले की दृष्टि से देखिए कि कोयले के दाम में सरकार ने जो कोल इंडिया लिमिटेड है, उसको 12.8 परसेंट बढ़ाने की अनुमति दी । जो एस०एस०सी०एल० है उसको 11.8 और इसका अर्थ यह हो गया कि जो कोयले का दाम पहले 322 रुपए प्रति टन था वह 364 हुआ और उसके बाद 434 रुपए प्रति टन हुआ है । इसमें संतोष की बात इतनी है कि जो साफ्ट कोयला होता है, जो डोमेस्टिक फ्यूअल के लिए यूज होता है उसको आपने नहीं बढ़ाया है । जनता को उसमें कुछ न कुछ राहत मिल सकती है लेकिन 28 दिसम्बर, 1991 के बाद, मतलब आपकी सरकार के आने के बाद एक बार बढ़ाने के बाद लगभग 14 महीने के अंदर आपने दूसरी बार कोयले के दाम 30 प्रतिशत बढ़ाए हैं और मैंने सरकार के तमाम पत्र ढूंढने की कोशिश की लेकिन इस 30 प्रतिशत दाम बढ़ाने का कोई उचित कारण बताया नहीं गया है और इसलिए मुझे लगता है कि अगर एक-तिहाई कोयले का दाम आप बढ़ायें और उसके बाद सरकार यह कहे कि इसका हिन्दुस्तान की कोयले की प्राईस पर असर मिनिमम होगा, बहुत कम होगा, लगभग नहीं के बराबर होगा तो मुझे लगता है कि जो भी मंत्री कोयले का दाम बढ़ाता है या किसी और चीज का दाम बढ़ाता है तो कम से कम उसमें धैर्य होना चाहिए कि वह उसके परिणामों के सामने आने का इंतजार करे ।

चीनी की तरह कोयला खाने की चीज नहीं है और इसलिए अगर चीनी महंगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा चीनी न लेकर आदमी उस महंगाई से बचने का प्रयास कर सकता है लेकिन जहां तक कोयले का सवाल है, कोयला अगर महंगा होगा तो उसका पूरी अर्थ नीति पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए जो कोयले को नहीं भी खरीदता है तो भी उसको महंगाई का असर झेलना पड़ता है । पहला असर झेलना पड़ेगा बिजली के रूप में ।

आपने जो कोयले का दाम बढ़ाया है उसका अभी तक जो अंदाज आया है उस अंदाज से यह लगता है कि बिजली पर प्रति किलोवाट 2.9 पैसे इसका भार पड़ेगा और मैं यह जानता हूं कि जितना वैधानिक भार होता है उससे ग्राहक के पास भार कई अधिक पड़ता है। कल्पनाथ जी, पावर मिनिस्ट्री से संबंधित थे, इसलिए वह जानते होंगे । इसलिए लगता यह है कि कोयले का दाम बढ़ने से कोयला जिस चीज में उपयुक्त होता है जैसे बिजली है तो उसके दाम बढ़ने प्रारंभ हो जायेंगे और केवल महीने भर में प्रदेशों के विभिन्न बिजली बोर्ड अपने दाम बढ़ा देंगे जिसका कारण वे यह बतायेंगे कि चूंकि मूल कोयले का दाम बढ़ा है इसलिए अब हमें बिजली का दाम बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है । इसलिए हम बढ़ा सकते हैं । इसलिए अगर बिजली का दाम 3 पैसे प्रति किलोवाट बढ़ने वाला है तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह मिनिमम है ? अब मंत्री महोदय यह भी जानते हैं कि कोई आदमी यह तो कह सकता है कि चीनी का दाम बढ़ेगा तो चीनी बिना रह जाऊंगा लेकिन वैसे ही अगर कोई आदमी यह भी कहे कि बिजली बिना रह जाऊंगा, वैसे तो बिजली मिलती नहीं है इसलिए बहुत बार रहना भी पड़ता है, इसलिए अगर वह बिजली के बिना रहने का निर्णय करे भी तो भी इस निर्णय के पश्चात् भी बिजली से जो कल-कारखाने चल रहे हैं और उसमें जो बिजली के बढ़े हुए दामों के कारण जो अनगिनत वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, इस महंगाई के चक्र से वह बच नहीं सकता । इसलिए कोयले पर चलने वाले कारखाने तो सीधे 30 प्रतिशत प्रभावित हैं और जो कोयले से बिजली पैदा होती है, जिसका मूल्य 3 पैसे प्रति किलोवाट बढ़ेगा तो उसका आगे प्रभाव पड़ेगा । इस कोयले के दाम बढ़ने का प्रभाव स्टील इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा । अब स्टील इंडस्ट्री पर इसका परिणाम कम से कम 142

प्रति टन होने की संभावना है । स्टील वालों ने अभी अभी अपने दाम बढ़ाए हैं। अब अगर आप कोयले में 30 प्रतिशत वृद्धि कर दें तो वह स्टील के दाम बढ़ा देंगे। एक तरफ कोयले के दाम बढ़ने से बिजली के दाम बढ़े, उस के बाद कोयले और बिजली के दाम बढ़ने से स्टील के दाम बढ़े और फिर कोयले, बिजली और स्टील के दाम बढ़ने के कारण रेल के किराए बढ़े और फिर रेल के किराए बढ़ने के कारण सब चीजों के दाम बढ़े, हर चीज के दाम बढ़ेंगे, इस प्रकार की स्थिति आती है। इसलिए मुझे लगता है कि केवल कोयले के 30 प्रतिशत का होलसेल प्राइस इंडेक्स पर कम से कम .32 प्रतिशत प्रभाव होने की संभावना है। इसलिए कोयले का दाम बढ़ाकर, कोयले की खान में हाथ डालकर केवल हाथ काले नहीं होते हैं, उसके साथ साथ गरीब आदमी का मुंह काला होने की संभावना इससे निर्माण होती है क्योंकि यह जो जीवन का चक्र है उसमें कोयला बहुत महत्वपूर्ण अंग है । इसलिए मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार से विचार किया जाए तो कोयले और चीनी इन दो चीजों के दाम इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकना हमारे लिए असंभव होगा और इसलिए मैं यह चाहता हूं कि भारत सरकार, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बजट पूर्व वृद्धि से बजट को निरर्थक और बेईमानी और आंकड़ों का खेल न बनाएं। चीनी के कारण गरीब आदमी की जो मीठा खाने की कभी कभी संभावना होती है उस पर इतना बड़ा बोझ न डालें और कोयले के दाम बढ़ाकर आपने जो महंगाई के चक्र को जन्म दिया है इसको रोकने के लिए इस पर पुनर्विचार करें। यदि आप न करें और इसी प्रकार महंगाई की आग जलती रहेगी तो मुझे लगता है कि जो महंगाई की आग में जलने वाला सामान्य नागरिक है, कहीं इस आग में सरकार को जलाने पर उतारू न हो, इस पर आप गंभीरता से विचार करें। यही मेरी प्रार्थना है। मान्यवर, कोयले और चीनी के दाम बढ़ाने के संबंध में अल्पकालीन चर्चा इस सदन में हो रही है। यह बात सही है कि दोनों के दाम बढ़े। कारण उसके क्या हैं, अगर उसकी तह में हम जाएं तो मालूम होगा कि चीनी के दाम बढ़ने की जो बुनियादी वजह है वह यह है कि किसान जो बड़ी मेहनत से गन्ना पैदा करता है और गन्ने की फसल सर्दीयों में पैदा की जाती है, इसको मेहनत से पैदा किए हुए गन्ने को मिल तक पहुंचाने की जो नौबत आती है उसके लिए उसको भारी कष्ट उठाना पड़ता है । उसकी लागत का अंदाजा लगाना आपके लिए कठिन हो जाएगा। गन्ने के खेतों में पानी देना, बिजली का इस्तेमाल करना, गाड़ी का इस्तेमाल करना, गन्ना पैदा करने के लिए किसान का पूरा परिवार उसमें लगा रहता है और जो यह गन्ने की खेती है यह अन-इकानामिक होल्डिंग हैं। इसलिए किसान में भारी निराशा इसलिए भी हो गई है कि उसके गन्ने की उसको उचित कीमत नहीं मिलती।

श्रीमन, आप जानते हैं कि हमारा देश खेतिहर मुल्क है और उसमें देश के कई सूबों में जो शुगरकेन या गन्ना पैदा करने का काम है और उसमें चीनी बनाने का काम है वह बड़े पैमाने पर किया जाता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला देश है लेकिन जो किसान चीनी पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है उसकी कठिनाइयों को कोई नहीं समझता। उसकी मेहनत और उसकी लागत का पैसा उसको न मिले तो यह किसी भी सरकार के लिए मुनासिब नहीं है। फिर चीनी की जो नीति है सरकार ने हमेशा यह नीति अपनाई है कि जो मध्यम श्रेणी का मजदूर है, गरीब है उस पर बढ़ते हुए भावों का कोई असर न पड़े। यह नीति सरकार की हमेशा रही है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर आप गौर से देखें तो जो निम्न श्रेणी के लोग हैं उनका जो चीनी का कंजम्पशन है वह इतनी मात्रा में नहीं है, हमारे देहातों में, छोटे छोटे कस्बों में जो चीनी की खपत है वह बहुत कम है। हमारे गांवों में रहने वाली जो

[श्री प्रमोद महाजन]

आबादी है वह चीनी का बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं करती है। ये साल के 6 महीने गुड़ बनाते हैं, खांड बनाते हैं इनको चीनी खरीदने की नौबत नहीं आती। लेकिन चीनी का जो बड़ा भाग इस्तेमाल किया जाता है वह धनाढ्य लोगों के द्वारा किया जाता है। ये लोग ही बड़े पैमाने पर चीनी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो हिन्दुस्तान की 75 फीसदी आबादी जो है वह चीनी का मुश्किल से 5 परसेंट कंजम्पशन करती है। 30 फीसदी जो हमारे रिच लोग हैं, बड़े-बड़े धनाढ्य हैं, जिनके यहां बड़ी-बड़ी दावतें होती हैं, जिनके यहां 6-6 बार चाय पी जाती है, तरह-तरह की मिठाई बनती है, सुबह से शाम तक नये किस्म के पकवान बनाये जाते हैं उनके यहां ज्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है। वे इस पोजिशन में है कि ये चीनी के बड़े भाग को दे सकते हैं। मैंने जैसा कहा सरकार के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि किसान को गन्ने के दाम ठीक मिलें। इसलिए सरकार ने चीनी के दाम बढ़ाकर किसान को सहूलियत देने का एक इरादा बना लिया है। यह अच्छा और मुनासिब इरादा है। किसान के लिए इसके भाव बढ़ाना जरूरी है। अगर गन्ने के भाव नहीं बढ़ेंगे तो देश के अंदर उथल-पुथल हो जायेगी। इसका मुल्क की इकोनोमी पर क्या असर पड़ेगा इसका अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। आज चीनी हमारे दूसरे देशों को भी जाती है। जैसा मैंने कहा कि चीनी के दाम बढ़ा कर किसान की आर्थिक अवस्था को मजबूत किया है। किसान हमें नई मशीनें लगाकर, पेस्टीसाइडस के जरिये गन्ने को कीड़ों से बचाकर जो ज्यादा से ज्यादा चीनी हमें देते हैं इससे किसान की आर्थिक अवस्था मजबूत होती है। देश की इकोनोमी में लाभ पहुंचता है। यह कांग्रेस सरकार ने बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। अगर किसान मजबूत रहता है तो सारा देश मजबूत रहता है। अगर किसान कमजोर रहता है तो देश मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए भी सरकार ने चीनी के दाम बढ़ा कर किसानों को फायदा पहुंचाया है इससे कोई आर्थिक बहुत बड़ी कठिनाई नहीं आती है। 75 फीसदी किसानों को नाराज नहीं किया जा सकता है। इससे देश मजबूत बनता है। गरीब आदमी की बात की जाती है, जाकर देखिये वह दिन में कितनी बार चाय पीता है, कितनी बार चीनी का इस्तेमाल करता है। जैसा मैंने कहा जो बड़े लोग हैं वे ही चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जिनको महंगाई से कोई मतलब नहीं वे इसको खूब इस्तेमाल करते हैं। जिनके पास बहुत पैसा है उनके सामने सवाल यह है कि रुपये को कैसे खर्च किया जाए। अगर आप किसान को दाम नहीं देंगे तो हमारे देश की प्रगति रुक जायेगी, तरक्की के रास्ते बंद हो जायेंगे। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने उदारता की नीति अपना करके यह रास्ता खोला है। आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इसका अनोखा विलक्षण प्रभाव आने वाला है। देश बड़ा मजबूत होगा। मैं कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं हैं जब यहां के किसानों की आर्थिक अवस्था में बहुत ज्यादा सुधार होगा। यहां तो मुल्क के अंदर बेकार के मसलों पर हमारी ताकत, शक्ति खर्च की जाती है। आपको ताज्जुब होगा कि ला एंड आर्डर पर जितना हमारा रुपया खर्च होता है उतना देश की प्रगति पर, देश के विकास पर नहीं हो पा रहा है, देश को मजबूत करने में नहीं लग रहा है। पिछले 5-6 महीनों में पेट्रोल के बहाने तनख्वाहों पर, भत्तों पर, नोन सेक्योरिटी पर सारा पैसा खर्च किया जाता रहा है। यह कहा जाता है कि मुल्क का गरीब कमजोर हो रहा है, गरीब और गरीबी की तरफ जा रहा है। गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। वह भूल जाते हैं कि गरीबों को मिलने वाला सारा रुपया पेट्रोल पर, पुलिस फोर्स पर, उसके आवागमन पर खर्च किया जाता है। इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। जो मुखतलिफ पार्टियां हैं जिनके मनसूबे साफ नहीं हैं साम्प्रदायिकता का मसला बनाकर मुल्क की

ताकत को तोड़ना चाहते हैं। अभी आपने देखा कि बम्बई में दंगे हुए दिल्ली में दंगे हुए और जहां जहां पर भी दंगे हुए वहां पर करोड़ों का नुक्सान हुआ। इसका हम अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी मौजूदा सरकार इस मुल्क को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना चाहती है, डिफेन्स के तौर पर मजबूत बनाना चाहती है। हमारी सरकार दलितों और गरीब लोगों का और सामान्य लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहती है। कांग्रेस सरकार की और मौजूदा सरकार की यह नीति है।

कोल के दाम बढ़ाने की बात कही गई। कोयला खानों में मजदूरों को कोयला निकालने में कितनी कठिनाई होती है, यह मैंने खुद खानों में जा कर देखा है। लेकिन 20 साल पहले जो सिस्टम था उसमें बड़ा फर्क आया है। अब मजदूरों के लिए लाइफ इंश्योरेन्स, हैल्थ इंश्योरेन्स का प्रबन्ध किया गया है। कितना रुपया मजदूरों पर खर्च करना पड़ता है। बिजली और पानी का इंतजाम करना पड़ता है। अगर कोई एक्सीडेन्ट हो जाता है तो उनको जो रिलीफ दिया जाता है उसमें रुपया लगता है। सरकार यह पैसा देती है। आखिर सरकार यह रुपया कहां से लाये? नई नई टक्नीक निकल रही है। मजदूरों को जो मेहनत करनी पड़ती थी उसमें भी सुविधा हुई है। इस सब के लिए रुपया देना पड़ता है। पहले कोयला चोरी हो जाता था उसमें भी कमी आई है। बिना कीमत बढ़ाये ये काम करना बिलकुल नामुमकिन है। मजदूरों की और कोयले की प्रोटेक्शन के लिए इंतजाम किया गया है। इसलिए, हमें कोयल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। कोयले की क्वालिटी में भी सुधार आया है। बाजार में अब जो कोयला मिलता है उसकी कंडीशन अच्छी होती है। उसमें डस्ट कम होता है। पहले करीब करीब 20 प्रतिशत कोयला बर्बाद हो जाता था, चोरी हो जाता था। खानों की प्रोटेक्शन के लिए फोर्स लगाई गई है। कोयला हमारी राष्ट्रीय सम्पदा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भाव बढ़ाये गये हैं वे कोयला खान मजदूरों की भलाई के लिए बढ़ाये गये हैं और यह बढ़ोतरी कोई कष्टदायक भी नहीं है। किसानों और मजदूरों की भलाई के लिए यह काम किया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं और फिर कहना चाहता हूं कि किसानों के दिलों में इससे खुशी हुई कि उनको अब गन्ने के दाम ज्यादा मिलेंगे। उनके दिल में एक उमंग है। हमारी मौजूदा कांग्रेस सरकार की यही नीति है कि किसानों और मजदूरों का भला किया जाय।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल (उत्तर प्रदेश): मि० वाइस चेयरमैन, मैं समझता हूं कि इस पर बहस करते हुए श्री प्रमोद महाजन जी ने जो कुछ कहा है उसके बाद चीनी और कोयले पर सफेदी और कालिख के बारे में ज्यादा कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रह गई है। उन्होंने बहुत अच्छी फीगर्स दी है और मैं समझता हूं कि कोई बाहर का आदमी इसको सुनेगा तो वह कंविन्स हो जाएगा कि सरकार ने चीनी के मामले में जितना पैसा गन्ने के लिए किसानों को दिया उससे ज्यादा गरीब लोगों से तकरीबन दुगुना ले लिया। कोयले में भी यही किया गया है। मैं इस तफसील में न जा करके एक असूली बात की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। पिछले दस सालों से इसी तरह से बजट के पहले दाम बढ़ा दिये गये हैं जिससे हकीकी मायनों में जो पार्लियामेंट की गरिमा है, पार्लियामेंट में बजट पेश करने का जो एट्रेक्शन होता है, असर होता है, अवाम पर भी और सरकार और ब्यूरोक्रेसी पर भी, वह आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि हमारे वक्त में भी कुछ ऐसे इकदामात हुए थे जिनको हमने क्रिटिसाइज किया था। लेकिन क्या ऐसी हालत पैदा हो गई है कि हमेशा बजट से पहले इस किस्म क

जो प्राइस राइज किया जाता है जिससे जनता को लूटने का काम किया जाता है। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मुल्क की स्थिति है जब यहां इस पर बहस हो रही थी कि यह डिसक्शन आज किया जाए या न किया जाए तो मुझे जरा भी गलतफहमी हुई कि जब बी० जे० पी० के लोगों ने कहा कि इस पर डिसक्शन आज नहीं होना चाहिये। फिर एक साहब ने कहा कि शायद प्रमोद महाजन जो सीरियस नहीं हैं। वह बात भी सामने आई। मैं समझता हूं अपनी गलती को मान लेना चाहिये। मेरा मानना यह है कि इस वक्त जो मुल्क की हालत है उसमें असल मुद्दा यह होना चाहिये कि मंहगाई क्यों हो रही है, आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ रहा है लेकिन इन सब बातों को छोड़ कर के कोयले को क्या आग लग रही है, चीनी से क्या आग पैदा हो रही है, हम उससे ज्यादा अयोध्या को आग में उलझे हुए हैं। मैं यह समझता था कि भारतीय जनता पार्टी जो इस आग को लगाने का काम करती है और आपने भी, त्वज्जोह लोगों को बंटी हुई है, एजेंडा बदल दिया। खाद का प्राइस बढ़ाया गया था, सब्सिडी खत्म की गई थी उसके बाद किसानों में एक असर हुआ था या फिर मंडल के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद अचानक कमंडल उठा उसी तरह से जैसे पहले मंडल आया था तो आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ऐसी लड़ाई जो बुनियादी लड़ाई है, हिन्दुस्तान में कामन आदमी, गरीब आदमी, 90 फीसदी लोगों की लड़ाई है उस पर कुछ मखसूस लोगों चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : जनता दल को कहिये।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : जनता दल के बारे में भी बता दूंगा। उनका मानना यह है कि एजेंडा शिफ्ट कर देना चाहिये और एजेंडा बड़ी कामयाबी से शिफ्ट कर दिया। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा प्रोफिट उनको नजर आ रहा है उसके अन्दर। इसलिए वह उसको ले कर के चल रहे हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि इस पूरे माहौल में जब पूरे मुल्क के अन्दर एक आग लगी हुई है, सरकार इस मुल्क के आवाम के साथ ऐसा धोखा कर रही है, जब लोगों की सारी त्वज्जोह बंटी हुई है तो आप प्राइस बढ़ा दीजिये, आप कोई भी दूसरा ऐसा काम कर दीजिये जिस पर ज्यादा त्वज्जोह न जाए। आप मंडल की बात न करिये, उसकी कोई जरूरत नहीं है इसलिए कि लोगों को इस वक्त न मंडल चाहिये और न यह चाहिये कि कितने दाम चीनी के बढ़ गये हैं, उनको इस चीज की फिक्र नहीं है। उनको किसी चीज की फिक्र नहीं है, उनको तो इस बात का फिक्र लगा दिया गया है कि मन्दिर बनेगा या नहीं बनेगी, मस्जिद बनेगी या नहीं बनेगी। आप भी पिछले तीन चार महीने से इसी काम में लगे हुए हैं। सरकार क्या कर रही है? उन मामलात को आगे बढ़ाते रहिये, सरकार को जैसे चलाना है चलाते रहिये। मैं समझता हूं प्रमोद महाजन जी ने इस पर अपनी स्पीच दी तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बड़े अदब के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितनी क्षमता आपके अन्दर है अगर आप वाकई आवामी मसलों को उठाएं तो आपको शायद इससे ज्यादा पापुलर्टी मुल्क में मिल सकती है। (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी ही राय मानेंगे।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : लेकिन आपने जो आग और खून का खेल चलाया है इससे आपको हिन्दुओं के एक सेक्शन में पापुलर्टी मिल सकती है, थोड़ा बढ़ावा मिल सकता है लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ कर के गुजारिश करूंगा कि आप एजेंडे को

शिफ्ट मत कीजिये। असल चीज यह है, असल लड़ाई यह है कि निचले तबके से जो ऊपर आना चाह रहे हैं उसको रोकने के लिए आप ख्वाहमखाह एक ऐसी कम्युनिटी को जिस पर अलीजमेंट का इल्जाम है कि जरूरत से ज्यादा रियायतें दी जा रही हैं रोज उसकी पोल खुलती है लेकिन प्रोपेगंडा इस तरह का है कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसको तो आपने कुर्बानी का बकरा बना रखा है। मैं यह मानता हूं कि इससे पहले भी अभी एक आर्डिनेंस सरकार ले कर आई थी और सरकार उसको पास भी कराना चाहेगी। उस आर्डिनेंस पर से त्वज्जोह हटाने के लिए क्योंकि उस आर्डिनेंस को न तो भारतीय जनता पार्टी ने माना था और न विश्व हिन्दू परिषद् ने माना था और न हिन्दुस्तान के किसी छोटे से छोटे मुसलमान ने उसको माना था। यहां तक कि मैंने तो यह भी कहा था कि आप यह जो आर्डिनेंस लाए हैं यह किस के मशविरे से ले कर आए हैं। तो एक बड़े वजीर ने कहा कि मुसलमानों में सिर्फ आप ही नहीं है मशविरा देने वाले, मुसलमानों में कुछ और भी लोग हैं मशविरा देने वाले 20-25 मुसलमान एम०पीज० ने कहा था कि इस मसले को अगर आप हल करना चाहते हैं तो इसको आप सील कर दीजिये और अदालत से फैसला करा कर खत्म कर दीजिये। उसको नहीं माना गया। आर्डिनेंस ले कर आ गए। उससे अपने वक्फ के ऊपर भी हमला कर दिया। उस आर्डिनेंस पर जब देख लिया कि हिन्दुस्तान को कोई भी मुस्लिम तंजीम उसके लिए तैयार नहीं थी चाहे मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल ला कान्फ्रेंस हो और चाहे जमाते उलमा हो वगैरह वगैरह हो, मैं सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस दे रहा हूं यह बताने के लिए कि किस तरह से त्वज्जोह बांटी जाती है। यहां तक कि कांग्रेस आई के अपने 21 मेम्बरान पार्लियामेंट हैं। मैंने उन वजीर साहब से गुजारिश की कि मुसलमान मेम्बर पार्लियामेंट जो आपके कांग्रेस के हैं उनसे आप वेलकम करा दीजिए.. (व्यवधान) मैं वहीं आ रहा हूं..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Mr. Afzal, kindly restrict yourself to the subject because we are already short of time. I would request you kindly to restrict yourself to the subject.

श्री मोहम्मद अफ़ज़ल उर्फ़ मीम अफ़ज़ल: तो उस वक्त मुझको ऐसा लगा कि ये जब कोई ऐसा काम करते हैं जो गलत काम होता है जो अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ होता है तो उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई दूसरा इश्यू खड़ा कर देते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि आर्डिनेंस से त्वज्जोह हटाने के लिए बम्बई का दंगा कराया गया। मैं यहां नहीं कहना चाहता हूं। सारा हिन्दुस्तान जानता है कि बम्बई के दंगे के अंदर कौन कौन लोग मुलव्वस थे। कोई एक्शन किसी के ऊपर नहीं हुआ और सदर साहब के कुनबे में कहां गया है जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज उसमें इन्वाल्व थी या पुलिस फोर्सेज कोई एक्शन उनके ऊपर नहीं हुआ। लेकिन प्रेजीडेंट साहब से कहलवाया जा रहा है... (व्यवधान)

मेरा कहना यह है कल्पनाथ जी और पांजा साहब, दोनों बहुत ही सीनियर लोग हैं, आप देखिए बुनियादी चीज यह है कि पार्लियामेंट में आपको भी रहना है, पार्लियामेंट में हमको भी रहना है। अगर पार्लियामेंट की गरिमा को आप खत्म कर देंगे, इस बजट की सेंक्टिटी को आप खत्म कर देंगे तो यह मसला इस तरह से हल होने वाला नहीं है। जो बजट आप लाते हैं उसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। आप इस तरह से पहले पढ़ाते हैं। पूरे सिस्टम के ऊपर असर होता है कि फलां तारीख को बजट आयेगा। एक साधारण आदमी भी यह मानके बदलता है कि इस बजट में इतनी बढ़ोत्तरी हुई है और मेरा बजट यह रहेगा। सब चीजें उस पर डिसाइड हुआ करती थीं। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसी परम्परा खराब चल रही है।

श्री मोहम्मद अफजल ऊर्फ मीम अफजल]

मैं सिर्फ एक सजेश्न देना चाहता हूं कि कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए कि सरकार द्वारा इस बीच में, चाहे किसी की सरकार हो, इस तरह के प्राइस राइज पर पाबंदी लगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आन प्राइस राइज बननी चाहिए। अगर सरकार किसी वक्त यह महसूस करती है कि किसी एक पटिक्युलर कमोडिटी के ऊपर प्राइस बढ़ाना बहुत जरूरी है तो इमीडियेटली वह जो कमेटी बनाई जाए पार्लियामेंट की उससे इस सिलसिले में बात की जाए । वह सारे फैक्टस एण्ड फिगर्स को देखे। अगर यह जरूरी हो कि प्राइस को बढ़ाना जरूरी है तो यकीनन वह बढ़ा दे। मैं समझता हूं कि इससे पार्लियामेंट की गरिमा भी कायम रहेगी और सरकार की परेशानी जायज है तो वह भी हल होगी। लेकिन जिस नीति को आप चला रहे हैं उसमें यह पासिबुल नहीं है। फिर आपके हाथ में तो प्राइस है नहीं। अब तो अमेरिका से प्राइस कंट्रोल कराएंगे सारा। डंकन आने के बाद तो ब्लू प्रिंट आ रहा है सी.आई.ए. का, उसको आप जिस दिन पास करा कर ले जाएंगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। सही कहा है किसी ने कि पोलिटिकल आजादी हमको मिली है लेकिन आर्थिक गुलामी आप लिखवाने वाले हैं अमेरिका के हाथ।

मैं इन अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे बोलने का मौका मिला। मैं कहता हूं कि मेरी एक डिमांड है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्राइस राइज पर बननी चाहिए जिससे बगैर पूछे सरकार इस किस्म की प्राइस पर कोई बढ़ोत्तरी न कर सके। शुक्रिया।

†شری محمد افضل عرف م۔ افضل (اتر پردیش)

مسٹر وائس چیئرمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بحث کرتے ہوئے شری پرمود مہاجن جی نے جو کچھ کہا ہے اس کے بعد چینی اور کوئلے پر سفیدی اور کالک کے بارے میں زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ انہوں نے بہت اچھی فیگرس دی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی باہر کا آدمی اس کو سنے گا تو وہ حیران ہو جائے گا کہ سرکار نے چینی کے معاملہ میں جتنا پیسہ گنے کے لئے کسانوں کو دیا۔ اس سے زیادہ غریب لوگوں سے تقریباً دوگنا لے لیا۔ کوئلے میں بھی یہی کیا گیا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہ جا کر کے ایک اصولی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پچھلے دس سالوں سے اس طرح سے بجٹ کے پہلے دام بڑھا دیئے گئے ہیں جس سے حقیقی معنوں میں جو پارلیمنٹ کی گریما ہے۔ پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کرنے کا جو اٹریکشن ہوتا ہے اثر ہوتا ہے

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

توجہ لوگوں کی بٹی ہوئی ہے۔ ایجنڈا بدل دیا۔ کھاد کا پرائس بڑھایا گیا تھا۔ سبسیڈی ختم کی گئی تھی۔ اس کے بعد کسانوں میں ایک اثر ہوا تھا یا پھر منڈل کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد اچانک کنڈل اٹھا۔ اسی طرح سے جیسے پہلے منڈل آیا تھا۔ تو اڈوانی جی نے رتھ یاترا شروع کی تھی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی لڑائی جو بنیادی لڑائی ہے ہندوستان میں کامن آدمی۔ غریب آدمی ۹۰ فیصدی لوگوں کی لڑائی ہے اس پر کچھ مخصوص لوگوں چاہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہوں یا کانگریس کے ہوں۔۔۔ "مداخلت"۔۔۔

شری کلپ ناتھ رائے: جنتا دل کی کہیے۔

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: جنتا دل کے بارے میں بھی بتا دوں گا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ایجنڈا شفٹ کر دینا چاہیے اور ایجنڈا انھوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ شفٹ کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جتنا سوچا بھی نہیں تھا اس سے زیادہ پروفٹ ان کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر۔ اس لیے وہ اس کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ اس پورے ماحول میں جب پورے ملک کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے سرکار اس ملک کے عوام کے ساتھ ایسا دھوکہ کر رہی ہے۔ جب لوگوں کی ساری توجہ بٹی ہوئی ہے تو آپ پرائس بڑھا عوام پر بھی اور سرکار اور بیوروکریسی پر بھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسکے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ میں یہ کہنے کیلئے تیار ہوں کہ ہمارے وقت میں بھی کچھ ایسے اقدامات ہوئے تھے جن کو ہم نے کریٹی سائز کیا تھا لیکن کیا ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیشہ بجٹ سے پہلے اس قسم کا جو پرائس رائز کیا جاتا ہے جس سے جنتا کو لوٹنے کا کام کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی اسستھی ہے جب یہاں اس پر بحث ہو رہی تھی کہ یہ ڈسکشن آج کیا جائے یا نہ کیا جائے تو مجھے ذرا سی غلط فہمی ہوئی کہ جب بی۔ جے۔ پی کے لوگوں نے کہا کہ اس پر ڈسکشن آج نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک صاحب نے کہا کہ شاید پرمود مہاجن جی سیریس نہیں ہیں۔ یہ بات بھی سامنے آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کی حالت ہے اس میں اصل مدا یہ ہونا چاہیے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے۔ عام آدمی پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کو چھوڑ کر کہ کوئلے کی کیا آگ لگ رہی ہے۔ چینی سے کیا آگ پیدا ہو رہی ہے۔ ہم اس سے زیادہ ایودھیا کی آگ میں الجھے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو اس آگ کو لگانے کا کام کرتی ہے اور آپنے بھی ——

ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کروں گا کہ آپ ایجنڈے کو شفٹ مت کیجئے۔ اصل چیز یہ ہے اصل لڑائی یہ ہے کہ نچلے طبقے جو اوپر آنا چاہ رہے ہیں اس کو روکنے کے لئے آپ خواہ مخواہ ایک ایسی کمیونٹی کو جس پر اپیزمنٹ کا الزام ہے۔ ضرورت سے زیادہ رعائتیں دی جا رہی ہیں روز اس کی پول کھلتی ہے۔ لیکن پروپیگنڈا اس طرح کا ہے کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو تو آپ نے قربانی کا بکرا بنا رکھا ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ابھی ایک آرڈی ننس سرکار لے کر آئی تھی اور سرکار اس کو پاس بھی کرانا چاہے گی۔ اس آرڈیننس پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کیونکہ اس آرڈیننس پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کیونکہ اس آرڈیننس کو نہ تو بھارتیہ جنتا پارٹی نے مانا تھا اور نہ وشو ہندو پریشد نے مانا تھا اور نہ ہندوستان کے کسی چھوٹے سے چھوٹے مسلمان نے اس کو مانا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ یہ جو آرڈیننس لائے ہیں یہ کسی کے مشورے سے لے کر کے آئے ہیں۔ تو ایک بڑے وزیر نے کہا کہ مسلمانوں میں صرف آپ ہی نہیں ہیں مشورہ دینے والے۔ مسلمانوں میں کچھ اور بھی لوگ ہیں مشورہ دینے والے۔ ۲۰-۲۵ مسلمان ایم۔ پیز نے کہا تھا کہ اس مسئلہ کو اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سیل کر دیجیے اور عدالت سے فیصلہ کرا کر ختم کر دیجیے۔ اس کو نہیں مانا گیا۔ آرڈیننس لے کر دیکھئے۔ آپ کوئی بھی دوسرا ایسا کام کر دیجئے جس پر زیادہ توجہ نہ جائے۔ آپ منڈل کی بات نہ کریئے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ لوگوں کو اس وقت نہ منڈل چاہیئے اور نہ یہ چاہیئے کہ کتنے دام چینی کے بڑھ گئے ہیں۔ ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ ان کو تو اس بات کا فکر لگا دیا ہے کہ مندر بنے گا یا نہیں بنے گا مسجد بنے گی یا نہیں بنے گی۔ آپ بھی پچھلے تین چار مہینے سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سرکار کیا کر رہی ہے۔ ان معاملات کو آگے بڑھاتے رہیئے۔ سرکار کو جیسا چلنا ہے چلاتے رہیئے۔ میں سمجھتا ہوں پرمود مہاجن جی نے اس پر اپنی اسپیچ دی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں بڑے ادب کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جتنی اکثمتا آپ کے اندر ہے اگر آپ واقعی عوامی مسئلوں کو اٹھائیں تو آپکو شاید اس سے زیادہ پاپولر پارٹی ملک میں مل سکتی ہے....

"مداخلت" ....

شری سنگھ پریہ گوتم: بہت بہت شکریہ۔ اب آپ کی ہی رائے مانیں گے۔

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: لیکن آپنے جو آگ اور خون کا کھیل چلایا ہے اس سے آپ کو ہندوؤں کے ایک سیکشن میں پاپولرٹی مل سکتی ہے۔ تھوڑا بڑھاوا مل سکتا ہے لیکن میں آپ سے

کے خطبے میں کہا گیا ہے کہ جو میرا ملٹری فورسیز اس میں انڈالو تھیں یا پولیس فورسیز۔ کوئی ایکشن انکے اوپر نہیں ہوا۔ لیکن پریذیڈنٹ صاحب سے کہلوایا جارہا ہے... "مداخلت"...

میرا کہنا یہ ہے کلپناتھ جی اور پانجہ صاحب۔ دونوں بہت ہی سینیر لوگ ہیں۔ اب دیکھئے بنیادی چیز یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ کو بھی رہنا ہے۔ پارلیمنٹ میں ہم کو بھی رہنا ہے۔ اگر پارلیمنٹ کی گریما کو آپ ختم کردیں گے اس بجٹ کی سینکٹشی کو آپ ختم کردیں گے تو یہ مسئلہ اسطرح سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ جو بجٹ آپ لاتے ہیں اس کے بہت سارے افیکٹس ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح سے پہلے بڑھاتے ہیں پورے سسٹم کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو بجٹ آئے گا۔ ایک سادھارن آدمی بھی یہ مان کر چلتا ہے کہ اس بجٹ میں اتنی بڑھوتری ہوئی ہے اور میرا بجٹ یہ رہے گا۔ سب چیزیں اس پر ڈیسائڈ ہوا کرتی تھیں۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ایس پر میرا خراب چل رہی ہے۔

میں صرف ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے کہ سرکار دوارا اس پیچ میں چاہے کسی کی سرکار ہو اس طرح کے پرائس رائز پر پابندی لگے میں سجیسٹ کرونگا کہ ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی آن پرائس رائز بننی چاہیے۔ اگر سرکار کسی وقت یہ محسوس کرتی ہے آگئے۔ اس سے آپنے وقف کے اوپر بھی حملہ کردیا۔ اس آرڈیننس پر جب دیکھ لیا کہ ہندوستان کی کوئی بھی مسلم تنظیم اس کے لیے تیار نہیں تھی چاہے مسلم پرسنل لا بورڈ ہو۔ چاہے مسلم پرسنل لا کانفرنس ہو اور چاہے جمیعۃ العلماء ہو وغیرہ وغیرہ ہوں۔ میں صرف ایک پاسنگ ریفرنس دے رہا ہوں یہ بتانے کیلئے کہ کس طرح سے توجہ بانٹی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کانگریس آئی کے اپنے ۲۱ ممبران پارلیمنٹ ہیں میں نے ان وزیر صاحب سے گذارش کی کہ مسلمان ممبر پارلیمنٹ جو آپ کے کانگریس کے ہیں ان سے آپ ویلکم کرا دیجیے۔ ... "مداخلت" میں وہیں آرہا ہوں...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Mr. Afzal, Kindly restrict yourself to the subject because we are already short of time. I would request you kindly to restrict yourself to the subject.

محمد افضل عرف م۔ افضل: تو اس وقت مجھ کو ایسا لگتا کہ یہ جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو غلط کام ہوتا ہے جو عوام کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوتا ہے تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی دوسرا ایشو کھڑا کردیتے ہیں۔ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ آرڈیننس سے توجہ ہٹانے کیلئے بمبئی کا دنگا کرایا گیا۔ میں یہاں نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ سارا ہندوستان جانتا ہے کہ بمبئی کے دنگوں کے اندر کون کون لوگ ملوث تھے۔ کوئی ایکشن کس کے اوپر نہیں ہوا۔ اور صدر صاحب

کہ کسی ایک پرٹیکلر کموڈٹی کے اوپر پرائس بڑھانا بہت ضروری ہے تو امیڈیٹلی وہ جو کمیٹی بنائی جائے پارلیمنٹ کی اس سے اس سلسلہ میں بات کی جائے۔ وہ سارے فیکٹس اینڈ فیگرس کو دیکھیں۔ اگر یہ ضروری ہو کہ پرائس کو بڑھانا ضروری ہے۔ تو یقیناً وہ بڑھا دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پارلیمنٹ کی گریما بھی قائم رہیگی اور سرکار کی پریشانی جائز ہے تو وہ بھی حل ہوگی۔ لیکن جس نیتی کو آپ چلا رہے ہیں اس میں یہ پاسیبل نہیں ہے۔ پھر آپ کے ہاتھ میں تو پرائس ہیں نہیں۔ اب تو امریکہ سے پرائز کنٹرول کرینگے سارا۔ ڈنکن آنے کے بعد تو بلیو پرنٹ آرہا ہے سی آئی۔ اے۔ کا اس کو آپ جس دن پاس کرائے جائینگے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ پولیٹیکل آزادی ہم کو ملی ہے لیکن آرتھک غلامی آپ لکھوانے والے ہیں امریکہ کے ہاتھ۔

میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بولنے کا موقع ملا۔ میں کہتا ہوں کہ میری ایک ڈیمانڈ ہے کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی پرائس رائز پر بننی چاہیے۔ جس سے بغیر پوچھے سرکار اس قسم کی پرائس پر کوئی بڑھوتری نہ کرسکے۔ شکریہ۔

श्री मोहम्मद तलीम (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, हम बजट से पहले बढ़ायी गयी महंगाई के बारे में, कीमतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह सरकार जो यह वादा करके आई थी कि सौ दिन के अंदर कीमतें घटायेंगे वह पिछले 17-18 महीने से देश के लिए इतना खतरा बन गई है कि ऐसे कोई भी नहीं है कि उसने खुद कीमतों में इजाफा न किया हो। प्रशासनिक आदेश, निर्देश से एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस बढ़ाये गये, कीमतें बढ़ायी गई हैं। बाहर जिन कीमतों पर सरकार नियंत्रण नहीं करती उनको भी बढ़ाने में इनके जो क्दामात थे वे काफी हद तक मदद करते हैं ताकि महंगाई बढ़ती रहे। अभी जब बजट सेशन बुला चुका गया था, समन हो गया था उसके बाद हुकूमत की तरफ से कोयला और चीनी की कीमतों में इजाफा किया गया। इससे पहले स्टील में पांच प्रतिशत का इजाफा किया गया। जनवरी महीने में गेहूं और चावल की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई। हमने सुबह भी यह बात उठाने की कोशिश की थी कि यह सिर्फ कोयले या चीनी का सवाल नहीं है। यह सरकार किस नजरिए से देखती है यह सवाल है। हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है उसे ये बह जगह नहीं देना चाहते हैं जहां इस बारे में चर्चा हो, बहस हो। सरकार जो कदम उठा रही है वह पार्लियामेंट की पीठ के पीछे के हैं। अभी अफसोस यह है कि हमारे देश में ऐसी ताकत हैं जो बहुत सी ऐसी नीतियां, ऐसे रास्ते अख्तियार करना चाहती है संसद की उसकी जो गरिमा है उसको घटाना चाहते हैं। उस पर वह चर्चा नहीं करना चाहते और हकूमत भी कैसे उन ताकतों से लड़ेगी, मुझे नहीं मालूम। जो ऐसे पालिसी डिसीजन लेते हैं, जो संसद् में आने से, प्रतिनिधियों का सामना करने से या जनता का सामना करने से डरते हैं कोयला व चीनी की जो कीमत बढ़ाई गई है, स्टील की जो कीमत बढ़ाई गई है, वह सब जानते हैं। सरकार का आंकड़ा यह कहता है कि जो मुद्रा-स्फीति है उसकी दरे में वृद्धि हो जाएगी। इसका कास्केटिंग इफैक्ट होता है हरेक मामले पर खुद अभी कहा गया मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन कोयले की जो कीमत बढ़ी है, उसकी कीमत में इजाफा होने से, सिर्फ यह बात नहीं है

सी.ए.आई. के कोयले में 322 से बढ़ कर 364 रुपए वृद्धि हुई, यह अब जो 383 रुपए टन का जो कोयला था वह 434 रुपए पर टन हुआ। उसका प्रभाव अभी जिस रोज वह निर्णय लिया गया उसी वक्त लोगों ने कैलकुलेट करके यह बता दिया कि पर यूनिट बिजली में 2.9 पैसे अर्थात् 3 पैसे का इजाफ़ा होगा। स्टील जो 5 प्रतिशत की दर में वृद्धि के कारण एक हजार रुपए प्रति टन बढ़ चुका कोयले की कीमत की वजह से इस पर 142 रुपए प्रति टन उसमें इजाफ़ा होगा। प्राइस इंडेक्स भी आगे जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होल सेल प्राइस इंडेक्स। रेल कंपनी जो कह दिए जाफर शरीफ जी, 50 करोड़ का इजाफ़ा हो गया रेल बजट कल आने वाला है। वह जो रेल का कीमत बढ़ाया जाएगा उसमें यह कोयले का, पांजा जी का भी थोड़ा हाथ उसमें रेल दफ्तर तक पहुंच जाएगा। कीमत में इजाफ़ा हो गया ऐसी बात नहीं है, सिर्फ कीमत में नहीं, रेल दफ्तर यह भी कह दिया कि जो स्टीम इंजन है उसको अब तेजी से हटाया जाएगा, क्योंकि खर्च ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसमें छंटनी भी और ज्यादा तेजी से जो जाएगी। एक-एक आदेश से, निर्देश से वह कई काम इसमें इजाफा होता जा रहा है। सरकार का आंकड़ा कहता है 16 जनवरी जो साल खत्म हुआ हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स सरकारी आंकड़ा के मुताबिक 16.8 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, सरकार सिर्फ अगर वह एक साल जो 16 जनवरी को खत्म हुआ 1992 में जो अपने हाथ के जरिए कीमत बढ़ाती है, बनियों को छोड़ दें, महाजनों को छोड़ दें आप...(व्यवधान)...तो वह 5 प्रतिशत वृद्धि होती। सरकार अपने पांच से खींच कर 6.8 पर ले गई। जो सरकार बाहर जाकर जनता से यह कहती है कि वह महंगाई को घटाएगी, चीनी की कीमत पिछले 5 साल, पांच रुपए दस पैसे जो पी.डी.एच. के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बांटी जाती है, जो सरकार यह वायदा करके आई थी कि वह पी.डी.एच. को और भी मजबूत करेगी और गरीब जनता के लिए करेगी और अब भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया कि पी.डी.एस. को बहुत मजबूत किया जा रहा है 5 रुपए 10 पैसे फर्स्ट जनवरी, 1988-89 साल से पहली जनवरी, 5 रुपए 25 पैसे 91 साल के 24 जुलाई 6 रुपए 10 पैसे प्रति किलो, 16 फरवरी, 1993 6 रुपए 90 पैसे से करके 8 रुपए 30 पैसे पहुंचा दिया गया।

श्री मोहम्मद सलीम : (पश्चिमी बंगाल) : अमन में सरकार को शूगर की बीमारी लग गई है।

श्री मोहम्मद सलीम : हां, डायबिटीज है। और यह भी कहा जाता है जब पहले कभी, इस बार पता नहीं मंत्री जी कल्पनाथ राय जो क्या तर्क होंगे ...(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : गन्ने का दाम क्या था।...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : एडमिनिस्टर्ड प्राइस जो बढ़ाया जा रहा है केन्द्र सरकार का यह कहना था उस समय आपके मंत्री का...(व्यवधान) कीमत में इजाफा इसलिए करते हैं कि लोग जरूरत से ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वह घट जाएगा। पता नहीं सरकार का क्या सोच है? पता नहीं कैसे यह कहा जाता है कि कपड़े की कीमत अगर हम बढ़ा देते है तो लोग आहिस्ता-आहिस्ता नंगा फिरते रहेंगे, चीनी की कीमत अगर बढ़ा देंगे तो चीनी की जो खपत है वह कम हो जाएगी, कोयले की कीमत अगर बढ़ा देंगे तो कोयले की खपत कम हो जाएगी? इस तरह से वह देश को आगे ले जायेंगे? लेकिन खुद जो सरकार इतने दिन तक जो कांग्रेस पार्टी यह कहती आई है कि आप उत्पादन में वृद्धि कीजिए, अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी यह कहा गया उस बारे में, यह तो बाद में चर्चा जब होगी तो आएगा कि कीमत में प्रभावी प्रभाव पड़ा है, चूंकि हमारा, हम पूरे विश्व में चीनी में अभी सचाई भी दे गए चौधरी जी कि पूरे विश्व में हम एक

[श्री मोहम्मद सलीम]

नंवर के उत्पादक देश हो गए हैं और नतीजे के तौर पर जो चीनी उत्पादन करता है उसको चीनी के बाजार से बाहर खींचकर निकाला गया। अब कल्पनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश से आए हैं, वह कह रहे हैं कि गन्ना उत्पादकों के लिए कीमत में कितना इजाफा कर दिया गया है।

श्री संघ प्रिय गौतम : उपाध्यक्ष जी, सारा सदन खाली है। कोई सदस्य नहीं है इनका, ट्रेजरी बैंचेज के मंत्रियों को छोड़कर।

श्री कल्पनाथ राय : आप और हम तो है।

श्री मोहम्मद सलीम: इससे यह पता चलता है कि मंहगाई के सवाल को वह कितनी गंभीरता से लेते हैं और आप भी कितनी गंभीरता से लेते हैं, यह भी पता चलता है क्योंकि आपके दल का दूसरा कोई और नहीं है। उपाध्यक्ष जी, अभी महाजन जी ने हिसाब कर के बताया कि जितना आप किसानों के लिए प्रोक्यूरमेंट प्राइस बढ़ाते हैं, उस तरह से वह नहीं होता है। अभी चीनी की या कोयले की कीमत जो बढ़ायी गयी है, वह कोयला जलने से मैनुफैक्चरिंग यूनिट से जो सामान निकलकर आएगा, उसमें कास्ट भी प्लस करते हैं। पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत जिस तरह बढ़ती है उससे डी०टी०सी० को किराए में और ज्यादा इजाफा करने का मौका मिल जाता है। इसी तरह से आपने चीनी मिल मालिकों को मौका दिया है। लेव्ही का जो रेशियो आपने बदला है, वह उनके हित में बदला है। अब मैं उसके हिसाब में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने उनको इतना फायदा देने के लिए चीनी की कीमत 8 रुपए 30 पैसे कर दी है। तो यह जो आंसू बहा रहे थे आप गन्ने के किसानों के लिए, लेकिन रामपोला में गोली चलायी थी। उनका 300 करोड़ रुपए का बकाया था और अपने वहां राष्ट्रपति शासन लगाया है। चाहे वहां भा०ज०पा० की सरकार आए या आपकी सरकार चले, लेकिन चीनी मिल मालिकों को आपने मजबूर नहीं किया कि उनके रुपए उनको वापिस मिलने चाहिएं।

श्री कल्पनाथ राय: वह मिल गए हैं।

श्री मोहम्मद सलीम : कागज में तो आपने दिखा दिया है कि गन्ना उत्पादक जो किसान हैं, हम उनको कितना फायदा करते हैं।

श्री कल्पनाथ राय : मिल गया उनको रुपया।

श्री मोहम्मद सलीम : अफसोस तो यह है कि लोग आप पर विश्वास नहीं करते।

श्री कल्पनाथ राय : आप जैसे लोग हैं तो कैसे करेंगे?

श्री मोहम्मद सलीम: उपाध्यक्ष जी, चीनी की कीमत में इजाफा हो या आप चांदी को बाहर से लाने के लिए रास्ता दें या पिछले डेढ़ साल से सरकार जो भी कदम उठा रही है, चाहे वह कैरोसीन और एल०पी०जी० की डुअल पालिसी का हो, मैंने टेलिविजन पर सुना कि मंत्री जी कहते हैं कि वह बाहर ब्लैक में एल.पी.जी. सिलेंडर 125 रुपए में खरीदते हैं तो मल्टी-नेशनल को अगर हम दे देते हैं और वह यहां आकर अगर वह 125 या 130 रुपए की दर से बेचता है तो उसमें नुकसान क्या है?

श्री मोहम्मद अमीन : नुकसान यह है कि बाहर वह 200 रुपए में बिकने लगेगा।

श्री मोहम्मद सलीम : उपसभाध्यक्ष जी, सरकार क्या कहना चाहती है? अगर गलत हो रहा है, अगर आपका सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, अगर स्मगलिंग हो रही है, सोने की, अगर वहां पर चोरी हो रही है, तस्करी हो रही है तो आप उसको रोकेंगे नहीं? नई लिबरलाइज्ड पालिसी का मतलब यह है कि विश्व बैंक और आई०एम०एफ० जो कह रहा है और भारत सरकार जिसको निगम रही है, वह यह है कि देखो हम स्मगलिंग बंद नहीं
पर आफिसियल स्टाम्प लगा दो। ब्लैक

मार्केटिंग बंद नहीं कर सकते, इसको एक आफिसियल स्टाम्प लगा दो । जो दो नंबर है उसको एक नंबरी कर दो और जो एक नंबरी है उसको खत्म कर दो। जाहिर बात है कि आपके अंदर अगर कुछ एक नंबरी लोग बचे हुए हैं तो वह भी नहीं रहेंगे क्योंकि दो नंबरी लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : आप उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद सलीम : समर्थन का सवाल नहीं है। समर्थन कौन किसका कर रहा है ? आपको लग रहा है कि मैं समर्थन कर रहा हूं । यहां दो दफ्तर के मंत्री जी बैठे हैं और हमारे जो संसदीय कार्य विभाग के मंत्री हैं वह मिनस्ट्री आफ फाइनेंस में भी हैं, मैं कहना चाहता हूं कि संसद सत्र के शुरू होने से पहले इस तरह से सरकार ने "फेरा" कानून को खत्म कर दिया, सत्र के पहले बाहर से जो सामान आएगा, आप कहते हैं कि हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं है । हम कहते हैं कि जो तस्करी आइटम्स हैं, उनको घटाओ । आप कहते हैं कि हम पूरी अर्थ नीति को मोड़ दे रहे हैं। उच्च तकनीकी लोग बाहर से आयेंगे और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, तस्करी गुड्स हैं, उसमें भी आपने कस्टम ड्यूटी को हटाकर छूट की है। यह बजट के पहले ही किया है जोकि बजट में शमिल होना चाहिए था यह पालिसी का सवाल है जिसे कि आप अपने आप खत्म कर रहे हैं। पार्लियामेंट के सामने आने से पहले खत्म कर रहे हैं। कैरोसिन और कुकिंग गैस के बारे में अभी मैंने कहा कि जब वह कहते हैं कि दो किस्म का होगा। नीला होगा और दूसरे किस्म का होगा। तो हर जगह पर हम यही कह रहे हैं कि सरकार की जो अर्थनीति है, वह एलिट-बायस्ड है। ऐसे कर रहे हैं कि आम जनता को हम नहीं पहुंचायेंगे, चाहे वह कोयला हो, चाहे कैरोसीन हो चाहे गैस हो, लेकिन सौ में से आधे लोग जो हैं उनके लिए बहुत एक्सीलेण्ट अरेंजमेंट रहेगा । हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो 125/– रुपए तो क्या 525/– रुपए देकर भी एल.पी.जी. कुकिंग गैस खरीद सकते हैं और उनके लिए थोड़ा अच्छे जार में, मल्टीनेशनल कंपनी का लेबल लगाकर उसको बेचने का अधिकार देंगे । मगर जो मध्यवर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको मामूली सी जो इस्तेमाल की चीज हैं, वह भी देने से इंकार कर रहे हैं। इस पालिसी को बहुत तेजी से लागू किया जा रहा है और यह सब कुछ किया जा रहा है पांच बिलियन या छह बिलियन या नौ बिलियन डालर भीख के लिए। आई० एम०एफ० के पास, वर्ल्ड बैंक के पास जाकर जो आप ने नए कर्ज लेने का रास्ता निकाला है, उसके तहत यह सरेण्डर है । हम, भारत की संसद इस बात को ठीक से तय नहीं करेगी । आपने विश्व बैंक, आई०एम०एफ० की शर्त मानी हैं कुछ बिलियन डालर के लिए और आप उनके सामान का हमारे बाजार में आने का बंदोबस्त कर रहे हैं। इतने दिन तक आपकी पार्टी के महान नेता यह कहते रहे कि आयल सेक्टर में, तेल के क्षेत्र में हमारा देश आत्म निर्भर बनेगा और अब आप विदेशी कंपनी को दावत दे रहे हैं। आप यह जिस दबाव के कारण कर रहे हैं, हम आपसे यह कहते हैं कि उस दबाव के विरोध में आप खड़े होइए और अपने पैरों की ताकत पर कुछ खड़े होने की कोशिश कीजिए।

महोदय, हमारे साथी जो इधर बैठे हुए हैं, यहां आकर जो कह रहे हैं, इस सदन के अंदर यह महंगाई की बात करते हैं, यह लोग विश्व बैंक या आई.एम.एफ. की जो सरायत हैं उस बारे में नहीं कहते अब अगर मैं यह कहूं तो गलत नहीं होगा, चीनी की कीमत आपने बढ़ाई । बंबई के फसादात का कुछ अफजल साहब ने जिक्र किया तो उससे ऐसा लगता है कि वह बाहर की बात में चले गए। सही बात है, नहीं जाना चाहिए, । लेकिन शूगर मिल के जो बेरन हैं बंबई में बैठे हुए, बंबई के राइटस देखकर आपको डर यह लगा, अब वह शिव सेना ले जायेंगे या बी.जे.पी. ले जायेंगे या आप उनको पकड़ेंगे। उनको कितनी किफायत आप दे सकते हैं,

[श्री मोहमद सलीम]

दोनों में रस्साकशी हो रही है। कितना देंगे, जनता को लूटने के लिए कौन कितना देंगे ? जनता को लूटने के लिए आपने अधिकार दिए खुले बाजार में। महाजन जी, अभी यहां थे, इतना कुछ कह गए पी.डी.एस. के बारे में, लेकिन आखिर में कह गए, कि डिलाइसेंसिंग कर दो और चीनी खुले बाजार में बिकेगी। अगर खुले बाजार में बिकेगी, जैसा आपने कॉस्ट एनालायसिस किया तो फिर यह 8 रुपए 30 पैसे से कम में बाजार में बिकनी चाहिए, महाजन और सेठ खुले बाजार में चीनी 8 रुपए 30 पैसे से कम में बेचते, लेकिन 8 रुपए 30 पैसे से कम में वह बेचते नहीं। वह चाहते हैं रेशो चेन्ज करके 45:55 को 40:60 करना और आप उसको हण्डरेड परसेंट खुले बाजार में ले जाना चाहते हैं। इसी का वह टग आफ वार चल रहा है और हमारे लिए परेशानी है कि गरीब जनता के सवाल को आप नहीं देख रहे हैं। जो हजारों करोड़ों रुपए की थैली लेकर वैरन पीछे आपके खड़े हैं, उनके लिए आप करना चाहते हैं। मैं यह बात अगर कहूं तो दूसरे सदस्य नाराज नहीं होंगे। (समय की घंटी)...

महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं जो बात कह रहा हूं, इस बारे में दलील पेश नहीं कर सकता, लेकिन 4 दिसम्बर को, अयोध्या काण्ड से पहले, मैं उत्तर प्रदेश गया था फैजाबाद जाने के लिए, गिरफ्तार कर लिया गया, तो एक हिन्दी अखबार है जो उत्तर प्रदेश में काफी चलता है उसमें पहले पेज पर यह लिखा था—लाखों कारसेवक अयोध्या पहुंच गए और दूसरा महत्वपूर्ण आइटम उसमें था—बाजार में तेज भाव शुरू हो गया। लाखों कारसेवक पहुंच गए अयोध्या में और बाजार तेज हो गया। अब कारसेवक को लेकर आपने कैसे क्या किया वह सबको मालूम है, लेकिन बाजार में तेज भाव करने के लिए आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे, देश की जनता बैठकर तमाशा नहीं देखेगी। आप ऐसी स्थिति तैयार कर रहे हैं, जहां गरीब लोगों का जीना दुश्वार होता जा रहा है। हम आप से यह कहते हैं कि आप इससे बाज आयें, इस हरकत से आप बाज आयें, आप जनता से कट चुके हैं, अब तो जनता के बारे में कुछ सोचिए। धन्यवाद।

श्री محمد سلیم (پشچمی بنگال): آپ سبھا ادھیکش مہودے۔ ہم بجٹ سے پہلے بڑھائی گئی مہنگائی کے بارے میں قیمتوں کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں۔ وہ سرکار جو یہ وعدہ کر کے آئی تھی کہ سو دن کے اندر قیمتیں گھٹائیں گے وہ پچھلے سترہ اٹھارہ مہینے سے دیش کے لیے اتنا خطرہ بن گئی ہے کہ ایسے کوئی سو روز نہیں ہیں کہ اس نے خود قیمتوں میں اضافہ نہ کیا ہو۔ پرشاسنک آدیش زدیش سے ایڈمنسٹریٹیو پرائس بڑھاتے گئے قیمتیں بڑھائی گئیں ہیں۔ باہر جن قیمتوں پر سرکار نیئنترن نہیں کرتی ان کو بھی بڑھانے میں انکے جو اقدامات تھے وہ کافی حد تک مدد کرتے ہیں تاکہ مہنگائی بڑھتی رہے۔ ابھی جب بجٹ سیشن بلا چکا گیا تھا۔ سمن ہو گیا تھا اس کے بعد حکومت کی طرف سے کوئلہ اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ اس سے پہلے اسٹیٹ میں پانچ پرتی شت کا اضافہ کیا گیا۔ جنوری مہینے میں گیہوں میں اور چاول کی قیمتوں میں بڑھوتری ہوئی۔ ہم نے صبح بھی یہ بات اٹھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ صرف کوئلے اور چینی کا سوال نہیں ہے۔ یہ سرکار کس نظریے سے دیکھتی ہے یہ سوال ہے۔ ہماری جو پارلیمنٹ ہے۔ سنسد ہے۔ اسے یہ وہ جگہ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ جہاں اس بارے میں چرچا ہو بحث ہو۔ سرکار جو قدم اٹھا رہی ہے۔ وہ پارلیمنٹ کی بحث کے پیچھے کے ہیں بھی نہیں

روپے پر فی ٹن بڑھ چکا۔ کوئلے کی قیمت کی وجہ سے اس پر ۱۴۲ روپے پر فی ٹن اس میں اضافہ ہوگا۔ پرائس انڈکس بھی آگے جائیگا۔ کنزیومر پرائس انڈکس۔ ہول سیل پرائس انڈکس۔ ریل کمپنی جو کہہ رہے۔ جعفر شریف جی۔ ۵۰ کروڑ کا اضافہ ہوگا ہوگیا۔ ریل بجٹ کل آنے والا ہے۔ وہ جو ریل کا قیمت بڑھایا جائیگا۔ اس میں یہ کوئلے کا پانچا جی کا بھی تھوڑا ہاتھ اس میں ریل دفتر تک پہنچ جائیگا۔ قیمت اضافہ ہوگیا ایسی بات نہیں۔ صرف قیمت میں نہیں ریل دفتر نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو اسٹیم انجن ہے اس کو اب تیزی سے بنایا جائیگا۔ کیونکہ خرچ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس میں چستی بھی اور زیادہ تیزی سے ہو جائے گی۔ ایک ایک آویشن سے۔ نرویش سے۔ وہ کمی کام اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سرکار کا آنکڑا کہتا ہے ۱۶ جنوری جو سال ختم ہوا ہمارا جو ہول سیل پرائس انڈکس سرکار آنکڑے کے مطابق ۱۶ اعشاریہ ۸ پر فی شت وردھی ہوئی تھی۔ سرکار صرف اگر وہ ایک سال جو ۱۶ جنوری کو ختم ہوا ۱۹۹۲ میں جو اپنے ہاتھ کے ذریعے قیمت بڑھاتی ہے۔ بنیوں کو چھوڑ دیں۔ جماجنوں کو چھوڑ دیں آپ... "مداخلت"... تو وہ ۵ پر فی وردھی ہوتی ہے۔ سرکار اپنے پانچ سے کھینچ کر ۱۶ اعشاریہ ۸ پر لی گئی جو سرکار باہر جا کر جنتا سے یہ کہتی ہے کہ وہ مہنگائی گھٹائیگی۔ چینی کی قیمت پچھلے یہ ہے کہ ہمارے دیش میں ایسی طاقتیں ہیں جو بہت سی ایسی نیتیاں۔ ایسے راستے اختیار کرنا چاہتی ہیں جو سنسد کو اس کی جو گرمائے اسکو گھٹانا چاہتے ہیں۔ اس پر وہ چرچا نہیں کرنا چاہتے اور حکومت بھی کیسے ان طاقتوں سے لڑے گی۔ مجھے نہیں معلوم۔ جو ایسے پالیسی ڈیسزن لیتے ہیں۔ جو سنسد میں آنے سے۔ پرتی نِدھیوں کا سامنا کرنے سے یا جنتا کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کوئلہ و چینی کی جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں۔ اسٹیل کی جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ سرکار کا آنکڑا کہتا ہے کہ جو معرا انڈیکس ہے اس کی درمیں وردھی ہو جائے گی۔ اس کا لٹنگ امپکٹ ہوتا ہے۔ ہر ایک مطالعے پر خود بھی کہا گیا میں اس کو دوہرانا نہیں چاہتا۔ لیکن کوئلے کی جو قیمت بڑھی ہے اس کی اہمیت میں اضافہ ہونے سے صرف یہ بات نہیں ہے۔ سی آئی۔ اے۔ کے کوئلے میں تین سو بائیس سے بڑھ کر تین سو چونسٹھ روپے کی وردھی ہوئی۔ اب جو تین سو اٹھاسی روپے فی ٹن کا جو کوئلہ تھا۔ وہ چار سو چونتیس روپے پر ٹن ہوا۔ اس کا پربھاؤ ابھی جس روز وہ نوٹیفکیشن لیا گیا اسی وقت لوگوں نے کیلکولیٹ کر کے یہ بتا دیا کہ پر یونٹ بجلی میں دو اعشاریہ نو پیسے ارتھات ۲۷ پیسے کا اضافہ ہوگا۔ اسٹیل جو ۵ پر فی شت کی درمیں وردھی کے کارن ایک ہزار

ہیں تو لوگ آہستہ آہستہ ننگے پھرنے لگیں گے۔ چینی کی قیمت اگر بڑھا دیں گے تو چینی کی جو کھپت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ کوئلے کی قیمت اگر بڑھا دیں گے تو کوئلے کی کھپت کم ہو جائیگی۔ اس طرح سے وہ دیش کو آگے لے جائیں گے۔ لیکن خود جو سرکار اتنے دن تک جو کانگریس پارٹی یہ کہتی آئی ہے کہ اتپادن میں ورّدھی کیجیے۔ ابھی راشٹرپتی کے ابھی بھاشن میں یہ بھی کہا گیا اس بارے میں یہ تو بعد میں جو چرچا جب ہوگی تو آئیگا کہ قیمت میں پربھاوی بڑھاؤ بڑا ہے۔ چونکہ ہمارا ہم پورے وشو میں چینی میں۔ ابھی بدھائی بھی دے گئے چودھری جی کہ پورے وشو میں ہم ایک نمبر دیش ہو گئے ہیں۔ اور نتیجہ کے طور پر جو چینی اتپادن کرتا ہے۔ اس کو چینی کے بازار سے باہر کھینچ کر نکالا گیا۔ اب کلپناتھ جی جو کہ اتر پردیش سے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہے کہ گنّا اتپادکوں کیلئے قیمت میں کتنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔

شری سنگھ پریے گوتم: اپ ادھیکش جی سارا سدن خالی ہے۔ کوئی سد سے نہیں ہے۔ ان کا ٹریزری بینچیز کے منتریوں کو چھوڑ کر۔

شری کلپناتھ رائے: آپ اور ہم تو ہیں۔

شری محمد سلیم: اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہنگائی کے سوال کو وہ کتنی گنبھیرتا سے لیتے ہیں اور آپ بھی کتنی گمبھیرتا سے لیتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ آپ کے دل کا دوسرا کوئی اور نہیں ہے۔ پانچ سال۔ پانچ روپے دس پیسے جو بی۔ ڈی۔ ایس۔ کے ذریعے سارو جنک وترن پرنالی کے ذریعے بانٹی جاتی ہے۔ جو سرکار یہ وعدہ کر کے آئی تھی کہ وہ بی۔ ڈی۔ ایس۔ کو اور بھی مضبوط کریگی اور غریب جنتا کے لیے کریگی۔ اور اب بھی راشٹرپتی کے ابھی بھاشن میں یہ کہا گیا کہ بی۔ ڈی ایس کو بہت مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ۵ روپے ۱۰ پیسے فرسٹ جنوری ۱۹۸۸-۸۹ سال میں سے پہلی جنوری ۵ روپے ۲۵ پیسے ۹۱ سال کے ۲۴ جولائی ۶ روپے ۱۰ پیسے پرتی کلو ۱۶ فروری ۱۹۹۲ ۶ روپے ۹۰ پیسے سے لیکر ۸ روپے ۴۰ پیسے پہنچا دیا گیا۔

شری محمد امین: اصل میں سرکار کو شوگر کی بیماری لگ گئی ہے۔

شری محمد سلیم: ہاں۔ ڈائبیٹیز ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے جب پہلے ابھی اس بار پتہ نہیں منتری جی کلپ ناتھ رائے جی کیا ترکہ دینگے "مداخلت"...

شری کلپ ناتھ رائے: گنّے کا دام کیا تھا... "مداخلت"...

شری محمد سلیم: ایڈمنسٹرڈ پرائس جو بڑھایا جا رہا ہے۔ کیندر سرکار کا یہ کہنا تھا کہ اس سمے آپ کے منتری کا... "مداخلت" قیمت اضافہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ضرورت سے زیادہ جو استعمال کرتے ہیں وہ گھٹ جائے گا۔ پتہ نہیں سرکار کا کیا سوچ ہے۔ پتہ نہیں کیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کپڑے کی قیمت اگر ہم بڑھا دیتے

شری محمد سلیم: افسوس تو یہ ہے کہ لوگ آپ پر وشواس نہیں کرتے۔

شری کلپناتھ رائے: آپ جیسے لوگ ہیں تو کیسے کریں گے۔

شری محمد سلیم: اپ ادھیکش جی۔ چینی کی قیمت میں اضافہ ہو یا آپ چینی چاندی کو باہر سے لانے کے لیے راستہ دیں۔ یا پچھلے ڈیڑھ سال سے سرکار جو بھی قدم اٹھا رہی ہے۔ چاہے وہ کیروسین اور ایل۔ پی۔ جی۔ کی ڈوبل پالیسی کا ہو۔ میں ٹیلی ویژن پر سنا کہ منتری جی کہتے ہیں کہ وہ باہر بلیک میں ایل۔ پی۔ جی۔ سلینڈر ۱۲۵ میں خریدتے ہیں۔ تو ملٹی نیشنل کو اگر ہم دیدیتے ہیں اور وہ یہاں آکر وہ ۱۲۵ یا ۱۳۰ کی در سے بیچتا ہے تو اس میں نقصان کیا ہے۔

شری محمد امین: نقصان یہ ہے کہ باہر وہ ۲۰۰ روپے میں بکنے لگے گا۔

شری محمد سلیم: اپ سبھا ادھیکش۔ سرکار کیا کہنا چاہتی ہے۔ اگر غلط ہو رہا ہے اگر آپ کا سسٹم ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے۔ اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ سونے کی اگر وہاں پر چوری ہو رہی ہے۔ تسکری ہو رہی ہے تو آپ اس کو روکیں گے نہیں۔ نئی لبرلائزڈ پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ وشو بینک اور آئی۔ ایم۔ ایف۔ جو کہہ رہا ہے اور بھارت سرکار جس کو نگل رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو ہم اسمگلنگ بند نہیں کر سکتے۔ اپ ادھیکش جی۔ ابھی مہاجن جی نے حساب کر کے بتایا کہ جتنا آپ کسانوں کے لیے پروکیورمنٹ پرائس بڑھاتے ہیں۔ اس طرح سے وہ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی چینی کی یا کوئلے کی قیمت جو بڑھائی گئی ہے وہ کوئلہ جلنے سے مینوفیکچرنگ یونٹ سے جو سامان لے کر آئیگا۔ اس میں کاسٹ بھی پلس کرتے ہیں۔ پٹرول کی قیمت یا ڈیزل کی قیمت جس طرح بڑھتی ہے۔ اس سے چینی مل مالکوں کو موقع دیا ہے۔ لیوی کا جو رینیو آپ نے بدلا ہے۔ وہ ان کے بہت میں بدلا ہے۔ اب میں اس کے حساب میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن آپ نے ان کو اتنا فائدہ دینے کیلئے چینی کی قیمت ۸ روپے ۳۰ پیسے کر دی ہے۔ تو یہ جو آنسو بہا رہے تھے۔ آپ گلے کے کسانوں کیلئے لیکن رام بولا میں گولی چلائی تھی ان کا ۳۰ کروڑ روپیے کا بقایا تھا اور آپ نے وہاں راشٹرپتی ساسن لگا دیا ہے۔ چاہے وہاں بھاجپا کی سرکار آئے یا آپ کی سرکار جلے لیکن چینی مل مالکوں کو آپ نے مجبور نہیں کیا کہ ان کے روپیے ان کو واپس ملنے چاہیں۔

شری کلپناتھ رائے: وہ مل گئے ہیں۔

شری محمد سلیم: کاغذ میں تو آپ نے دکھا دیا ہے کہ گنا اتپادک جو کسان ہیں ہم ان کو کتنا فائدہ کرتے ہیں۔

شری کلپناتھ رائے: مل گیا ان کو روپیہ۔

ہونا چاہیے تھا۔ یہ پالیسی کا سوال ہے۔ جیسے کہ آپ اپنے آپ ختم کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے سامنے آنے سے پہلے ختم کر رہے ہیں۔ کیروسین اور کوکنگ گیس کے بارے میں ابھی میں نے کہا کہ اب وہ کہتے ہیں تو قسم کا ہوگا۔ نیلا ہوگا یا دوسرے قسم کا ہوگا۔ تو ہر جگہ پر ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی جو ارتھ نیتی ہے وہ ایلیٹسٹ رائٹ ہے۔ ایسے کر رہے ہیں کہ عام جنتا کو ہم نہیں پہنچا پائیں گے۔ چاہے وہ کوئلہ ہو چاہے کیروسین ہو۔ چاہے گیس ہو۔ لیکن سو میں سے آدھے لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت ایکسپلیٹ ایجنٹ رہے ہیں۔ ہمارے دیش میں ایسے لوگ ہیں جو 25 روپے تو کیا 525 روپے دیکر بھی لیں گے جی۔ کوکنگ گیس خرید سکتے ہیں۔ اور ان کے لیے تھوڑا اچھے بھارت میں ملٹی نیشنل کمپنی کا لیول لیول لگا کر اس کو بیچنے کا ادھیکار دیں گے۔ مگر جو نیچے ورگ کے لوگ ہیں۔ من ورگ کے لوگ ہیں ان کو معمولی سی جو استعمال کی چیز ہے وہ بھی دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس پالیسی کو بہت تیزی سے لاگو کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پالیسی پاتھ بلین یا نو بلین ڈالر ریٹ کے لیے۔ آئی۔ ایم۔ ایف۔ کے پاس اور ورلڈ بینک کے پاس جا کر جو آپ نے قرض لیے تھے کل راستہ نکالا ہے۔ اس کے تحت یہ سریندر ہے۔ ہم بھارت کی سنسد اس بات کو ٹھیک نہیں

چلو اس پر آفیشلی اسٹامپ لگا دو۔ بلیک مارکیٹنگ بند نہیں کر سکتے اس کو ایک آفیشل اسٹامپ لگا دو۔ جو دو نمبری ہے اس کو ایک نمبری کر دو اور جو ایک نمبری ہے اس کو ختم کر دو۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کے اندر اگر کچھ ایک نمبری لوگ بچے رہتے ہیں۔ تو وہ بھی نہیں رہیں گے کیونکہ دو نمبری لوگ آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شری سنگھ پریے گوتم: آپ ان کا سمرتھن کیوں کر رہے ہیں۔

شری محمد سلیم: سمرتھن کا سوال نہیں ہے۔ سمرتھن کون کس کو کر رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں سمرتھن کر رہا ہوں۔ یہاں دو دفتر کے منتری جی بیٹھے ہیں اور ہمارے جو سنسد ہے کارسے دے بھاگ کے منتری ہے وہ منسٹری آف مائینانس میں بھی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سنسد ستر کے شروع ہونے سے پہلے اس طرح سے سرکار نے "فیرا" قانون کو ختم کر دیا۔ ستر کے پہلے باہر سے جو سامان آئے گا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ودیشی مدرا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو کنٹینر آئٹم ہیں ان کو گھٹاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم پوری ارتھ نیتی کو منسوخ دے رہے ہیں۔ آج تک کتنی لوگ باہر سے آئیں گے اور جو کنزیومر ڈیوریبلس ہیں لگژری کلاس کی اس میں بھی آپ نے کسٹم ڈیوٹی کو ہٹا کر چھوٹ دی ہے۔ بجٹ کے پہلے کیا ہے۔ جو کہ بجٹ میں شامل

میں رسہ کشی ہو رہی ہے۔ کتنا دینگے۔ جنتا کو لوٹنے کے لیے۔ کون کتنا دیں گے۔ جنتا کو لوٹنے کے لیے آپ نے ادھیکار دیے کھلے بازار میں۔ مہاجن جی ابھی یہاں تھے اتنا کچھ کہہ گئے۔ پی۔ ڈی۔ ایس۔ کے بارے میں۔ لیکن آخر میں کہہ گئے کہ ڈی لائیسینسنگ کر دو اور چینی کھلے بازار میں بکے گی۔ اگر کھلے بازار میں بکے گی۔ جیسا آپ نے کہا ڈی کنٹرول اینڈ ڈیسنٹرلائیز کیا تو پھر یہ ۵ روپے ۴۰ پیسہ سے کم میں بازار میں بکنی چاہیے۔ مہاجن اور سنگھ کھلے بازار میں چینی ۸ روپے ۳۰ پیسے سے کم میں بیچیے لیکن ۸ روپے ۳۰ پیسے کم میں وہ بیچنے نہیں دیتے ہیں کہ ریشو چینج کر کے ۵۵:۴۵ کو ۴۰:۶۰ کرنا اور آپ اس کو ہنڈریڈ پرسینٹ کھلے بازار میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اسی کا وہ ٹگ آف وار چل رہا ہے۔ اور ہمارے لیے پریشانی ہے کہ غریب جنتا کے سوال کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جو ہزاروں کروڑوں روپے کی تھیلی لیکر بیوپاری پیچھے آپ کے کھڑے ہیں ان کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ بات اگر کہوں تو دوسرے سدسیہ ناراض نہیں ہونگے۔... "وقت کی گھنٹی"...

مہودے۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، اس بارے میں دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن ۴ دسمبر کو ایودھیا کانڈ سے پہلے۔ میں اتر پردیش گیا تھا۔ فیض آباد جانے کیلئے۔ گرفتار کر لیا گیا۔ تو ایک ہندی اخبار ہے۔ کرے گا۔ آپ نے ورلڈ بینک۔ آئی۔ ایم۔ ایف۔ کی شرط مانی ہے۔ کچھ بلین ڈالر کے لیے اور آپ ان کے سامان کا ہمارے بازار میں آنے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اتنے دن تک آپ کی پارٹی کے مہان نیتا یہ کہتے رہے کہ آئل سیکٹر میں۔ تیل چیمتر میں ہمارا ویشوں آئل نر بھر بنے گا اور اب آپ ورلڈ بینک کمپنی کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ یہ جس دباؤ کے کارن کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس دباؤ کے ورودھ میں آپ کھڑے ہوئے۔ اور اپنے پیروں کی طاقت پر کچھ کھڑے ہونے کی کوشش کیجیے۔

مہودے۔ ہمارے ساتھی جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں اگر جو کہہ رہے ہیں اس سدن کے اندر ہنگامی کی بات کرتے ہیں یہ لوگ ورلڈ بینک یا آئی۔ ایم۔ ایف۔ کی جو شرائط ہیں اس بارے میں نہیں کہیے۔ اب اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ چینی کی قیمت آپ نے بڑھائی۔ بمبئی کے فسادات کا کچھ افضل صاحب نے ذکر کیا تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ باہر کی بات میں چلے گئے۔ صحیح بات ہے۔ نہیں جانا چاہیے لیکن شوگر مل کے جو بیوپاری ہیں بمبئی میں بیٹھے ہوئے۔ بمبئی کے رائٹس کو دیکھ کر آپ کو ڈر یہ لگا۔ اب وہ شوسینا لے جائیں گے۔ یا بی۔ جے۔ پی لے جائیں گے۔ یا آپ ان کو پکڑ لیں گے ان کو کتنی کفایت آپ دے سکتے ہیں آپ دونوں

ہیں۔ ہم بیٹھ کر تماشہ نہیں دیکھیں گے۔ دیش کی جنتا بیٹھ کر تماشہ نہیں دیکھے گی۔ آپ اسی استھی تیار کر رہے ہیں۔ جہاں غریب لوگوں کا جینا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے باز آئیں اس حرکت سے آپ باز آئیں۔ آپ جنتا سے کٹ چکے ہیں۔ اب تو جنتا کے بارے میں کچھ سوچیے۔

دھنیہ واد۔

اتر پردیش میں کافی چلتا ہے۔ اسمیں پہلے پیج پر یہ لکھا تھا۔ لاکھوں کارسیوا ایودھیا پہنچ گئے۔ اور دوسرا ہیڈ لائن آئیٹم اس میں یہ تھا۔ بازار میں تیز بھاؤ شروع ہو گیا۔ لاکھوں کارسیوک پہنچ گئے ایودھیا۔ اور بازار میں تیز ہو گیا۔ اب کارسیوک کو لیکر آپ نے کیسے کیا کہا۔ وہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن بازار میں تیز بھاؤ کرنے کیلئے آپ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, before entering into the question of economics involved in this matter—my young friend, Mohammed Amin, was trying to just deal with it—the thing that struck me most was that these two increases were effected, one just six days before the Budget Session and the other I think about coal, just five days before the Budget Session of Parliament was to begin and the President was to make a speech before the Joint Session of Parliament. The address of the President is taken to be a statement of the general policies of the Government in the coming year, I should say, and I have been more confirmed on listening to the address of the President that this year particularly, it has reduced the President's speech really to a nullity, in the sence that it is an enumeration of events no question of policy, so to say on economic, financial and fiscal matters, even on the question of foreign relations, perhaps, some policy pertaining to our relations with Pakistan and such other States. This deliberate denigration of the institution of Parliament and the office of President is something which should be pondered over seriously even by the leaders of the Government, its consequences and where it will lead us to. Without trying just to make light of it, the summons was issued much earlier. Would heavens have fallen? I saw on the television, Mr. Kalpnath Rai's figure was shown on the screen. That is a sort of dummy, not a live picture. It is an endearing picture. But, what was said was that for three successive terms, the prices of sugarcane have been increased without effecting any increase in the price of sugar; therefore, this time, it has become inevitable. Perhaps, that was for the consumption of the TV viewers. When so many days could pass, why not six more days? Would the heavens have fallen? The same relates to coal also. Would the heavens have fallen? Soft coke has been exempted and the domestic consumers are not affected directly. (*Interruptions*) He is the past Energy Minister. The coal's all-pervasive power was explained by a young Member, Mr. Pramod Mahajan, in picturesque Hindi which I cannot naturally imitate. What colossal harm would have been done to Indian economy if these two acts were deferred by five and six days...or the question of LPG or kerosene, opening it for private trade? By taking this step towards privatisation they are trying to make a virtue of it, that it will rejuvenate the Indian industry, the Indian economy and what not, without giving an iota of proof in support of it. Could not this action of Caption Satish Sharma

have waited for another week? What was the urgency? They talked of a sentiment. It is not just a question of sentiment. It is a question of accountability to Parliament. Whether it is legal or illegal, that is another matter. But when you are facing Parliament, why don't you face Parilament with your own actions, with your own misdeeds? Everything will come under the scrutiny of the House, whether you want it or not. And if you do not want it, then try to devise a method by which Parliament has not be called. That is one aspect of the matter, a serious aspect of the matter.

The other part is what this price-increase will do for the common man. We are listening to repeated announcements, pronouncements and declarations that inflation has been totally controlled, that it has come to the lowest level since 1990. Now what will happen if these increases and other increases are in the offing? The Budget that will be presented will be a meaningless thing outside which every dubious and doubtful economic activity will be undertaken by the present Government. I think, that is the most important point. During the Budget the economic aspect, the fiscal aspect, and other things may be seriously looked into Isn't the Government answerable to these questions? Is it bypassing their policy? They said a question was raised during the Zero Hour in spite of the Short Duration Discussion. That is, in a way, the crux of the problem. The people have steeled themselves to face this Budgetary or non-Budgetary exercise which will make a heavy inroad into their daily life. They are unable to make both ends meet. They will not be able to make even one end meet after this. But who cares? There will be a concoction of inflation figure, there will be a concoction of cost of living index and there will be a concoction of the number of people below the poverty line, but all these concoctions will not take them very far. They are in the throes of a very dark cloud engulfing the country regarding which they are browing hot and cold. They allowed the Babri Masjid to be demolished and now they have imposed a ban on the rally proposed by the BJP in Delhi, but taking advantage of that provision they have put a ban on other rallies too. This approach, this process would take them very far. If they are able to face the facts wholly and clearly and enunciate their policies before the people clearly, if they can compel those who are able, to make some sacrifice, moneyed people, the people who are bleeding the common people white, are made to pay more, those who are able to pay are made to pay more and those who are not able to pay if they are enabled to, at least, lead their existence, they must find some way out otherwise I am not speaking of the October Revolution of 1917 but of the French Revolution which is called in the Marxist jargon "bourgeois democatic revolution".

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Sir, it will take a long time. You have already taken your time. Please try to be a little brief.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Sir, I am at the concluding stage. During the French Revolution it was said that the rulers of France in those days did not realise taxes from those who were able to pay but from those who were unable to pay and the result was the Revolution. Like that, the rulers of our country also once they remember that lesson, refresh their memory or recall that, may not commit the same reat mistake after more than 200 year. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Dr. Sivaji. Your party has been allotted four minutes only. So, kindly try to be brief.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir will you finish before 7 P.M.?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): I hope so.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Sir, since last August the administered prices of various commodities have been hiked and the total burden on the people is to the tune of Rs. 10,000 to Rs. 12,000 crores. Whether it is petroleum or sugar or issue price of foodgrains or steel or coal and the like, my point is that it does not have any sanction of the Parliament. On the one hand, the State Governments are penalised. Had the Government gone for a hike in the excise duty, the State Governments would have got their share out of the proceeds. But the Government found it convenient to hike the administered prices so that the State Governments may not get their share and the entire amount is grabbed by the Union Government. On the other hand, the State Governments are also affected whenever the administered prices of all the commodities are hiked because the bulk consumers are the State Governments. If they hike the prices of petroleum products all the State Road Transport Corporations will go into red. If the issue prices are enhanced the public distribution system in the States will get affected. Similarly, if the coal prices are raised the power generation in all the States will get affected. The State Governments do not get their share of these hikes and it is not reasonable and I hope that the Finance Commission will take note of this so that this distortion may be corrected. It is only to satisfy the whims and fancies of the IMF that the subsidy component is cut down and at the same time the Government in their wisdom found it convenient to collect more money by raising the administered prices. As far as sugar is concerned, the Government gave benefits to the mill owners. On the one hand, they reduced the levy sugar from 45g to 40g. and enhanced the free sale sugar from 55g. to 60g. So a leverage is given to the mill owners. On the other hand, the price of levy sugar has been raised by one rupee and forty paise for each kilogram. But at the same time the minimum support price of cane has been enhanced only by fifty rupees, i.e. from Rs. 260 to Rs. 310 per tonne. The fact is that the average recovery in all the sugar factories in the country is round about 10 per cent or a little more than 10 per cent. So, it is a fact that a tonne of sugar-cane yields a quintal of sugar. Out of that one quintal of sugar 40 kilograms are sold through the public distribution system at Rs. 8.40 which amounts to Rs. 332. And the remaining 60 kilograms are sold at the rate of Rs. 10 in the market. That gives Rs. 600. So the total value of the finished product in the form of sugar is Rs. 932 out of one metric ton of sugarcane. On the other hand, one metric ton of sugarcane gives 40 kilograms of molasses. And 40 kilograms of molasses yield 2.2 litres of absolute alcohol. The fact is that all the State Governments are dependent on the sugarcane growers. The late Cheif Minister of Andhra Pradesh, Shri T. Anjaiah,—he was also a Minister at the Centre—Commented when he was the Chief Minister of Andhra Pradesh, "Maharashtra is having so many factories and industries at Bombay, Pune and at other places. Likewise, Gujarat is having industries at Ahmedabad, Baroda, Surat and Tamil Nadu at Coimbatore and Madras. But Andhra Pradesh does not have any industry. Therefore, the only revenue available with the State Government is to sell the arrack and collect revenue." So, all the State Governments are diverting 80 per cent to 85 per cent of the total production of the molasses and absolute alcohol to arrack. To convert absolute alcohol to arrack is a simple mechanism of diluting the alcohol with water four times, five times or ten times. Therefore, what I want to say is that one metric ton of sugarcane gives more than Rs. 2000 in the form of excise duty to the State Government and another Rs. 1000 in the form of sugar. So, out of Rs. 3000 the minimum support price fixed by the Government is only Rs. 310. So, the sugarcane growers who are supplying raw material for all these products are getting less than 10 percent. What I mean to say is that India is number

one in the production of sugar. In the last four decades our production of sugar has gone up by 10 times. During the last decade our production of sugar has almost doubled. So, there is no meaning of having a dual price system for sugar. One is the public distribution system and the other is open market system. What I mean to say is that each family whether middle class, upper middle-class or lower middle-class, on an average consumes about 5 kilograms of sugar per month. So, if 5 kilograms of sugar is purchased from the open market or from the public distribution system, it does not matter much. Whenever the Central Government fix the minimum support price the State Governments feel that the minimum support price fixed by the Union Government is irrelevant. They fix their own States-advised prices. So, all the State Governments including the States coming under the Congress rule and also those States coming under the Governor's rule, enhance the price of sugarcane and suggest Rs. 500 or more than Rs. 500 as minimum guarantee price, or the State-advised price. So, when the writ of the Union Government does not work on the State Government, for the implementation of the minimum support price, there is no point in announcing a price here in Delhi which is not implemented at all at the lower level. But the difficulty here is that the difference between the minimum guarantee price and the minimum support price does not go into computation while fixing the price of levy sugar. I, therefore, suggest that it is the right time to give up the dual price system of sugar, one in the public distribution system and another in the open market. One more aspect I would like to add is that when the National Front Government was in office they gave relaxation for installation of new sugar factories. There was a rule that within 40 kilometres of an existing sugar unit no new unit is allowed. But the then Government has reduced the limit from 40 kilometres to 25 kilometres. Then a lot more of applications were received by the Union Government. Some applications were cleared as far as UP is concerned. Ninety-four applications from Andhra Pradesh are pending for the last three years for want of clearance. Each unit has a crushing capacity of more than 2,500 tonnes per day costing more than Rs. 40 crores. These applications are pending. If these applications are cleared, then more than Rs. 4000 crores will be pumped into the sugar industry as well as the sugarcane sector in Andhra Pradesh. I was surprised at the reply given by the predecessor of the present Minister. Last December I had asked him about the fate of the applications that were pending. The Minister replied that the applications got burnt in the-fire-accident in Krishi Bhavan and hence there were no more applications and that they were trying to build up the records once again. So, that was the reply given by the Minister in this august House. This shows the lack of seriousness of the Government in clearing the applications and augmenting the production of sugar. I hope we are not groping in the dark. I hope the present Minister will take necessary steps. Another aspect that I would like to add is that by 2000 AD our target is to produce something like 20 million tonnes of sugar. At this rate, with the phenomenon of good harvest and bad harvest and crop rotation and alternative cropping pattern, unless we give some incentive to the farmer to grow sugarcane he will not grow sugarcane but will switch over to other crops. In this connection I would like to suggest that zonal regulations should be lifted and the entire cane should be supplied to the sugar factories in the zones. In the present context, out of the total sugarcane produced in the country, less than 40 per cent is going to the sugar factories. The rest of it is going for our production, khandsari production and production of other varieties. If the farmer gets remunerative prices for his produce he will supply the cane to the sugar factories, thereby, production of sugar will be augmented and we can reach the tar-

[Dr. Yelamanchili Sivaji]

get by 2000 AD. 2000 AD is not very far and I hope the Government will take these points into consideration.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, our protest is on a number of reasons. Let us cut it short. Firstly, the method that is being repeatedly resorted to by the Government on the eve of the Budget is really dangerous. It has been a repeated practice with the Government to resort to extraordinary methods to give the Budget a better look or to white wash the other side, the negative aspects of the Budget. We know the compulsions of the Government. It is under the dictum of the World Bank to narrow down the fiscal deficit. Therefore, in order to help Shri Manmohan Singh to present a little more presentable Budget, this pre-Budget exercise is being done. This is extraordinary and unparliamentary. We cannot agree to it. Therefore, as a methodology we have no other alternative but to put on record our protest. That is about the format. But there is a content also. The content is the hike that has been resorted to by the Government. It is about the price of coal and sugar and another sector that is, the LPG sector. All this will lead to further fuelling of the inflation which the Government claims to have contained. If the coal price is increased, it will mean that the Railways are going to increase the fare and if they are going to increase the fare, there will be a general upward movement of the price level. Because of increase in the price of coal, cost of thermal generation is going to be higher and as a result, there is going to be an increase in the present cost. Therefore, it is not a price-hike of a particular commodtty. It is going to result in fuelling the price level. Therefore, this is an attempt to create a situation where inflation takes another full swing, and this is where our objection is. There was another route. There was an alternative. The hon. Minister instead of increasing the price of coal to cover the higher costs, could have sat down with the trade unions and with the administration and discussed ways to stop the pilferage. to stop wastage and to stop costs on other counts. But the general tendency with the hon. Ministers is to take the easiest course. Instead of tightening up the organisation and instead of getting better co-operation from the workers, the hon. Minister has definitely taken to the easiest way under the directions of the Government. His general reply is going to be that to meet the increased costs, the price of coal has been increased.

Let us take the case of sugar. I do not know who are the Ministers suffering from diabetes in the Government. I do not know. I do not have the health report of the Prime Minister. But the fact remains that this is a Government during whose tenure, the price of sugar has been increased by 60 per cent within a period of 18 months.

Therefore, Sir, this is an act of irresponsibility. Coal is consumed for thermal generation. Coal is consumed for transportation. Sugar is also essential in human life. And this has been singled out for increasing the price by the Government. This is where our quarrel is. It is not only on the question of form; it is also on the question of content.

Thirdly, what is the price level in the country? The Government things; that inflation has come down to 7 per cent. But if we base our calculations on the consumer price index, it is not less than 8.3 per cent. But that in a statistical jugglery. If we go to a consumer, if we go to a market, if we ask a housewife, if we go to a common man belonging to the lower rung of the society, the feeling is that despite the announcement and promise of the Government and despite the declaration that prices have declined, the consumer gets the commodity at a price which is higher than the price at which he used to purchase in the corresponding period of last year. Therefore, prices might have decreased for a Government statistician, prices might have decreased for the Finance Minister in the ensuing Budget, the prices have not decreased

so far as the common consumer is concerned. This step of the Government, this hike in the coal price, this hike in the sugar price and all that is in the offing, all that is up the sleeves of Dr. Manmohan Singh, will create a situation which is becoming or will become or almost has become intolerable for the common people.

Therefore, my point is, instead of going in for austerity, instead of going in for curtailment of the costs, instead of going in for a rigorous exercise, the Government has taken to the most simplified way of putting the burden on the common people. This is where we have a quarrel. This is where we protest. Let me tell the Government one simple truth. While we are fighting for secularism, we are not going to condone the economic fature and the economic irregularity of the Government. Don't believe that since we are in the same boat to fight for national integration, we are going to say okay to all that you do in the Budget, to all that you do in ters of your economic policy. We will oppose it tooth and nail. If necessary,—it is for the Government to take a decision if, in the ensuing Budget and, in future, in the formulation of economic policy, occasion so arises, we shall not falter to raise our voice, to put on record our disapproval of your policies, even if that means something else for the fate of the Government. I do not know. It is for the Government to decide. Things have come to a dangerous pass. The country has been brought to a disastrous situation. Therefore, the time has come for the people, who have become a little into learnt of the way you are leading the economic front of the country, to raise their voice. That is why, to record our disapproval, on the eve of the presentation of the Budget, we took this extraordinary course of raising a short duration discussion on the very first day when the Parliament has met. Thank you.

SHRI KALP NATH RAI: Respected Vice-Chairman, Sir, with effect from 17-2-1993, the retail issue price of levy sugar throughout the country has been revised from Rs. 6.90 per kg. which had been fixed in January, 1992, to Rs. 8.30 per kg. The increase of Rs. 1.40 per kg. in the issue price consists of 90 paise on account the increase in the statutory minimum price for sugarcane from Rs. 26 per quintal, applicable during the 1991-92 season, to Rs. 31 per quintal, applicable for the 1992-93 sugar year: 40 paise as ad hoc increase to recoup the deficit of Rs. 335 crores in the Levy Sugar Price Equalisation Fund Account of the Food Corporation of India, pertaining to earlier years; and 10 paise by way of increase in the distribution charges from the present level of 57 paise per kg. to 67 paise per kg.

The Commission on Agricultural Costs and Prices, in their report submitted at the end of August, 1992, had recommended the raising of the statutory minimum price for sugarcane from Rs. 26 per quintal to Rs. 29 per quintal for the 1992-93 season. However, subsequent to the receipt of that report, some further developments took place which persuaded the Government to increase the statutory minimum price by an additional Rs. 2 per quintal, over and above the CACP-recommended statutory minimum price. The first was the increase in the prices of petroleum products and the resultant increase in the cost of irrigation and transportation of sugarcane. The second was the 20 per cent increase in the procurement price of wheat for the 1993-94 marketing season, which was announced on 8th January, 1993. The reported fall in sugarcane production during the current agriculture year, compared with the previous agriculture year, of about 20 million tonnes also indicated that unless the support price for sugarcane is improved, the farmers may divert substantial areas to other crops thereby reducing the availability of cane for production of mill sugar. If this trend was allowed to continue, it would lead to a fall in the production and emergence of a deficit in the overall sugar availability relative to domestic demand. Due to reduced cane availability this

[Shri Kalp Nath Rai]

year, sugar production is likely to show a fall of about 15 lakh tonnes, compared to the output of 133 lakh tonnes achieved in 1991-92.

The average realisation of sugar mills was Rs. 770.92 per quintal in 1991-92, whereas the breakeven cost was Rs. 793.81 per quintal. As a result, a large number of mills suffered financial loss which eroded their capacity to liquidate the various liabilities including

7.00 P.M. cane price arrears to the farmers stood at Rs. 349.77 crores at the close of the 1991-92 season on 31.9.1992. U.P. alone, which produces over 35 per cent of the country's sugar, out of the total cane dues of Rs. 1750 crores in 1991-92 season nearly Rs. 230 crores stood in arrears as on 1.10.1992 (the start of the 1992-93 season). Many mills had to postpone their repairs on account of financial difficulties and started their crushing later than usual.

Recognising that sugar is an essential commodity which plays an important part to the lives of million of people, Government has taken a number of decisions including increase in the retail price of sugar to encourage sugar mills, to attoin financial viability and to optimise their production so that they can pay the cane prices to farmers promptly as delay in the settlement of cane arrears was resulting to the farmers losing interest to cane cultivation and diverting their cane areas to other crops.

Since a rise in the Statutory Minimum Price of sugarcane is accompanied by corresponding rise to the price of levy sugar which has to be paid to the mills, the question arose before the Govt. whether this increase in levy prices payable to the mills should be met cut of a budgetary subsidy which would leave the retail issue price or sugar unchanged for the consumers or whether this should be passed on to the consumers to the forms of a rise in the issue price of levy sugar. The Ministry of Finance was of the view that the available food subsidy should be used for subsidising the price of basic foodgrains like wheat, rice, Jawar, bajra and maize which are supplied through the public distribution system rather than diverting a portion of the subsidy for subsidising the price of levy sugar.

As regards the ad hoc increase of 40 paise per kg. which is intended to recoup the outstanding deficit of Rs. 335 crores as on 1-4-1992 standing in the account of levy Price Equalisation fund of FCI, this deficit has accumulated on account of the lag between announcement of higher Statutory Minimum Price of sugarcane in previous years which had not been accompanied by upword revision in the retail price of levy sugar within the same time frame.

Finally, the increase in 10 paise towards distribution cost of the levy sugar has been found necessary, because many States had reported that State nominees and wholesalers were reluctant to lift sugar from the sugar mills for onward supply to ration shops because the existing distribution charges did not enable them to recoup their transportation and handling expenses fully, is a result of which they were being burdened with financial losses.

In the light of the above, it would be seen that the revision in retail issue price of levy sugar has been effected keeping in view the larger interest of maintaining a healthy sugar economy in the medium terms.

Finally, it should be mentioned that if are able to mention a higher level of production and comfortable stocks of sugar, we can successfully even out the eydical fluctuations and maintain stability in open market sugar prices at present, because of comfortable stocks we are able to release sufficient quantity of sugar for free sale in the market to keep prices within a reasonable band and prevent then from showing any undue sharp increase.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Shri Ajit Kumar Panja.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Is it a reply?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): He has tried to cover all the points in one statement only. (*Interruptions*) Yes, Mr. Panja.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: Sir, almost all the speakers have raised a very preliminary point, saying that there was only a week for the Budget Session, "why did you increase the price of coal, why didn't you do it at the time of the presentation of the Budget?" Most respect fully I would like to submit for the consideration of the hon. Members to understand the difference between the Budget and the increase in the administered price of coal. Budget is for taxation and other reasons. There is no provision anywhere in the Indian law which provides that the increase of price should be during the Budget only. Also it has never been done so far as my knowledge goes, subject to correction. Therefore, a procedure has to be followed based on the law made by the Parliament, including by this very House. The law is that there is a control order by which a notification has to be issued. And that I quote, Sir—it is from the Colliery Control Order, which has got the blessings of both the Houses:

> "The Central Government may, by notification in the Official Gazette, fix the maximum or the minimum sale price, or both, subject to which coal may be sold by colliery owners, and any such notification may fix different prices (i) of different grades and sizes of coal, and (ii) for different collieries."

That is exactly what has been done. This should, have been done on or after the 28th of December, 1992. Within one year the notification should have been issued on that basis because the power has been given—a delegated power has been given by the Cabinet to the Coal Ministry that they can do so but there must be a guideline and that they cannot act on a caprice or whim. And what is the guidelines. There is an authority—the established authority of the BICP—Bureau of Industrial Costs and Prices. We need not go every year to the Cabinet but exercise the delegated authority which is under the Coal Ministry. Again, BICP is an independent authority, and experts are there, looking after the entire economy. Every paisa of increase that has been made, has been made exactly according to the norms set by the BICP and not a single paisa more than that.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Excuse me for a minute. What was their recommendation and what was your final hike?

SHRI AJIT KUMAR PANJA: Sir, the increase, as asked for by the hon. Member, is based on various indices. The first one is concerned with variable dearness allowance. I am sure the hon. Member will not disagree if payment is made out of this increased price to the miners who are arising the coal. The other indices are increase in import costs of power, explosives, petrol, oil and lubricants, other stores, depreciation, interest on long-term loans, return to equity and interest on working capital. The total import per-tonne comes to Rs. 41.31. We have rounded it of to Rs. 42, which comes to 12.8 per cent for coal India out of which the variable DA is Rs. 12.37.

SHRI SUNIL BASU RAY: Are you giving it to the workers now?

SHRI AJIT KUMAR PANJA: This is according to the previous agreement which was arrived at.

SHRI SUNIL BASU RAY: For the last two years you have not been speaking with the workers.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: The agreement which has been entered into, by which the increase has taken place, is RS. 12.37. The increase in the rate of variable dearness allowance, which has not yet been agreed to—as the hon. Member has pointed out—is not because of the fault of the Government but because mutual negotiations have to take place. It

[Shri Ajit Kumar Panja]

is pending—the other dearness allowance rate has not yet been agreed to Government did not allow the companies to raise their prices to 17.6 per cent but allowed only up to 12.8 per cent. And the price was allowed to be raiised by only 12.8 per cent exacity according to the norm and guideline given by the BICP. Therefore, although it should have been done on the 28th of December, 1992, why did we wait? We waited for the detailed consideration. As very rightly pointed out by Mr. Mahajan and some other hon. Members, if you touch the price of coal, so many other things are immediately affected. That is why, in the 51 days that we took, all the details were studied about how it is going to affect the wholesale price how much it is going to affect other prices etc. All the details were studied, and after studying them. It was found that so far as the impact on the power sector is concerned. It is estimated to be only 2.9 paise per kilowatt-hour. About steel. It is estimated to be Rs. 142 per tonne. The impact on the wholesale price index will be only of the order of 0.32 per cent.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: If the Minister will yield for a moment, let me point out two things, Sir. The Indian market, because of the highly inflationary situation, generally does not react in the proportion it should. Therefore, let the Minister not have the satisfaction that such a small or marginal increase which he claims to have done, is going to have only a little impact in the market. The market reaction is always volatile. It is always with hostility that the market reacts. Therefore, let us not believe that such an amount of increase will not bring about a bigger impact.

Secondly, Sir, let me put on record that this is what the Government has been claiming much before Mr. Panja took over. Whenever there was an increase in the coal price, at every point of time, it was the workers who had been singled out to be the beneficiaries. That is not the point, Sir. Other steps the coal management could have taken. This was not the only course to provide funds for providing additional benefits to the workers.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: I don't think so. The hon. Member is not right. So far as the present statistics are concerned, they indicate that the annual rate of inflation so far has been contained by this Government at around 7 per cent. This is not a minor achievement but, I think, it is a major achievement.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is for the Minister to give the figure, and it is for the people to know what the inflation is.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: It is said. "I do not believe, I do not believe." This has to be tested. If it is stated, "I do not believe it." I cannot make them believe it. But, Sir, My submission is this.

SHRI SUKOMAL SEN: Mr. Minister, will you yield for a minute?

SHRI GURUDAS GUPTA: Mr. Minister....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): I think the Minister is not yielding. You have already made the point. Let the Minister reply.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: I can only quote from the Press. The price of essential... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Please sit down. You have made your point. The Minister is not yielding. You have taken your time.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: I can quote a Press report, not a report, but an editorial that came out in one of the leading dailies in India, supporting immediate increase in the price before it was declared. It said that the increase is a must. Otherwise this public sector will be again in the red. The reason is to save this public sector. On the one hand you say. "You save the public sector." On the other hand you say,

"No, no. Even though the cost increases and everything else increases and we feel that the miners should be paid still, no increase should take place." That will not be able to save the public sector.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: That is not the point. What steps has the Government taken to curb the cost?

SHRI AJIT KUMAR PANJA: I can't have a question-and-answer session like this.

It had to be done by a notification, and it has been so done. Sir, we could have done it earlier, as I said. If we had done it earlier, Rs. 127.5 crores *The Coal India could have got from the* market because of this increase at 12.8 per cent. According to the Indices for increase upto 12.8 % the CIL would have got Rs. 2.5 crores per day. At Rs. 2.5 crores per day for 51 days it would have been Rs. 127.5 crores. We had the time. We could have done it immediately. But we had to have a decision, a conscious decision. We consulted the BICP and we took into consideration the entire gamut of what was going to happen. How is this going to affect? That is why we took time. That is why the consumer saved Rs. 127.5 crores. (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The Government has been too much generous. We must thank the Minister for the generosity.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: The point is, there is one way of attacking and another way is not realising—I hope hon. Members will realise. In that event what have we to do? We have to come up with latest indices. Latest indices were asked for by Mr. Mahajan and I have placed them before the house.

It has been stated that there will be a serious loss to the Railways and it will increase its fare also. No. We have found out from the Railways, that for the one-and-a-half month period of this financial year. It will be Rs. 4 crores only. These are some of the points which I want to place on record.

The other point, the hon. Members will realise, is what we are going to do with this public sector unit. The Budgetary support to Coal India during 7th Plan was 83 per cent. In the Plan outlay for Coal India during the 8th Plan, the Budgetary support has been reduced to 13.5 per cent.

On point that was raised was how it will benefit. This was the net receipt by Coal India. Coal India in 1991-92 became a net contributor. How? Its Budget was for Rs. 399 crores. Coal India paid Rs. 400 crores to Govt. in 1991-92. Even then its total net profit was Rs. 167 crores. So, this public sector enterprise has started gaining. So, this public sector enterprise, which has started contributing this year, other things being equal, may treble its contributions. When the price is being increased along with its efficiency, in contributions are bound to increase. Many studies have ween made to suggest how we may enhance its efficiency. Therefore, it is a turning-point for Coal India, the public sector limited company, In becoming a major contributor. If it becomes a major contributor, who gains out of it? It is being stated that the States would not gain by it. Its contributions will not go over to them. From there its gains are being distributed to various States.

The increase in the price became necessary because of the increase in the cost of inputs about which I have already stated in detail. Of the estimated cost of production, hon. Members will note, of Rs. 297.18 per tonne in the case of CIL, for the year 1991-92, 45.65 per cent was spent on wages 15.72 on stores; 10.89 on depreciation; 10.60 on interest; 7.44 on power, 3.54 on transport, 4.79 on administrative expences and 6.34 on miscellaneous items. Therefore, what is the elbow-room available to CIL? It is only 11.13 per cent. Over and above the CIL has attempted to bring down its cost. In fact, its cost in real terms had gone down by over 4 per cent last year. Therefore, Sir, taking all this

[Shri Ajit Kumar Panja]

into consideration, I cannot ask the CIL, direct the CIL to make any reduction so far as wages are concerned. Rather I have to tell them what I have done to increase the dearness allowance. Therefore, I have to increase the price of coal so that money is readily made available. Under these circumstances, it was absolutely necessary to increase the price of coal. That is why it has been done.

With regard to the standard of efficiency, it has to be taken note of. That is why I require the unanimous support of this House. Of course, I have taken note of the points made by the hon. Members.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: None of the Congress Members is present in the House. Whoever was itching for a discussion today itself is not present here. Only three Ministers are there ... (*Interruptions*).... So, Mr. Pania should try to get the support from his Benches.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: Mr. Mahajan is one of the movers of the Short Duration discussion. I have to satisfy him not the Members from my party. Sir, those are my submissions.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: That only indicates how isolated this Government is and his own party.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

(I) The Dentists (Amendment) Bill, 1992.

(II) The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 1992.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

(I)

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on Tuesday, the 23rd February, 1993, adopted the following motion in regard to the Dentists (Amendment) Bill, 1992, which was passed by Rajya Sabha on the 22nd December, 1992, and laid on the Table of Lok Sabha on the 23rd December, 1992:—

MOTION

"That this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to leave being granted by this House to withdraw the Dentists (Amendment) Bill, 1992 which was passed by the Rajya Sabha on the 22nd December, 1992 and laid on the Table of this House on the 23rd December, 1992".

(II)

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on Tuesday, the 23rd February, 1993, adopted the following motion in regard to the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 1992, which was passed by Rajya Sabha on the 22nd December, 1992 and laid on the Table of Lok Sabha on the 23rd December, 1992:—

MOTION

"That this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to leave being granted by this House to withdraw the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 1992 which was passed by the Rajya Sabha on the 22nd December, 1992 and laid on the Table of this House on the 23rd December, 1992."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Now the House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at twenty-two minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 24th February, 1993.